घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 185- गुरूवार 07 - मई 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

कैबिनेट की मंजूरी..वंदे मातरम गीत को राष्ट्रगान जैसा दर्जा मिला

अपमान करने या गायन में बाधा डालने पर सजा-जुर्माना,जन-गण-मन से पहले गाया जाएगा

नई दिल्ली,06 मई 2026। केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान 'जन गण मन' के समान दर्जा देने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की पहली बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार, बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम पर अब वही नियम और पाबंदियां लागू होंगी, जो वर्तमान में राष्ट्रगान पर लागू हैं। यानी इसके अपमान या गायन में बाधा डालने की स्थिति में सजा होगी। अभी राष्ट्रीय ध्वज,संविधान और राष्ट्रगान के अपमान पर जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है, और अब वंदे मातरम भी इसमें शामिल किया जाएगा।

कानून में बदलाव और सजा का प्रावधान

सरकार वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर यह बदलाव कर रही है। इसके लिए कानून की धारा 3 में संशोधन किया जाएगा। इस धारा के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगान गाने में बाधा डालता है या उसे रोकता है, तो उसे तीन साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। दोबारा अपराध करने पर कम से कम एक साल की सजा का प्रावधान है। संशोधन के बाद यही नियम वंदे मातरम पर भी लागू होंगे।

वंदे मातरम गाने को बढ़ावा देने का भी आग्रह

गृह मंत्रालय ने स्कूल-कॉलेज और महत्वपूर्ण संस्थागत कार्यक्रमों के दौरान वंदे मातरम गाने को बढ़ावा देने का भी आग्रह किया है इस कदम का उद्देश्य स्टूडेंट्स और आम जनता के बीच राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति जागरूकता और सम्मान को प्रोत्साहित करना है। यह भी बताया गया है कि जब वंदे मातरम का प्रदर्शन किसी बैंड द्वारा किया जाता है, तो उससे पहले ढोल की थाप या बिगुल की ध्वनि से औपचारिक रूप से गायन की शुरुआत का संकेत दिया जाना चाहिए।

सिनेमा हॉल और फिल्म स्क्रीनिंग के लिए छूट

साथ ही, मंत्रालय ने सिनेमा हॉल और फिल्म स्क्रीनिंग के लिए विशिष्ट छूट प्रदान की है। निर्देश के अनुसार, फिल्म के साउंडट्रैक के हिस्से के रूप में वंदे मातरम बजाए जाने पर दर्शकों को खड़े होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मनोरंजन स्थलों में दर्शकों को खड़े होने के लिए मजबूर करने से देखने का अनुभव बाधित हो सकता है।

सरकार ने जारी की गाइड लाइन

केंद्र सरकार ने बुधवार को भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन के लिए आधिकारिक प्रोटोकॉल के लिए गाइडलाइन जारी की। गाइड लाइन के अनुसार, वंदे मातरम का संपूर्ण आधिकारिक वर्जन, जिसमें छह श्लोक हैं और जिसकी अवधि लगभग 3 मिनट और 10 सेकंड है, प्रमुख राजकीय समारोहों के दौरान प्रस्तुत या बजाया जाना चाहिए। इनमें राष्ट्रीय ध्वज फहराना, राष्ट्रपति और राज्यपालों के आधिकारिक कार्यक्रमों में औपचारिक आगमन और प्रस्थान समारोह और ऐसे समारोहों में उनके निर्धारित भाषणों से पहले और बाद के कार्यक्रम शामिल हैं।

पहले 'राष्ट्रगीत' गाया जाएगा और उसके बाद 'राष्ट्रगान'

अगर किसी कार्यक्रम में 'वंदे मातरम' और 'राष्ट्रगान' दोनों होने हैं, तो पहले 'वंदे मातरम' (राष्ट्रगीत) गाया जाएगा और उसके बाद 'राष्ट्रगान' दिशा-निर्देशों में आगे यह भी स्पष्ट किया गया है कि दर्शकों से अपेक्षा की जाती है कि वे सम्मान के प्रतीक के रूप में दोनों प्रदर्शनों के दौरान सावधान मुद्रा में खड़े रहें।

बंगाल में नई सरकार का तैयारियां शुरू,ब्रिगेड ग्राउंड में होगा आयोजन

बंगाल में 9 मई को भाजपा सरकार की शपथ समारोह

कोलकाता,06 मई 2026। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम कोलकाता के प्रतिष्ठित ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, शपथ समारोह में प्रधानमंत्री, एनडीए व भाजपा के सभी मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। दो दर्जन मंत्री भी शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों में वोटिंग के बाद 4 मई को मतों की गणना हुई। जिसमें सत्ता धारी दल तृणमूल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के साथ ही राज्य में तृणमूल कांग्रेस के 15 साल लंबे शासन का अंत हो गया है। आंकड़ों की बात करें तो टीएमसी को मात्र 80 सीटें मिली हैं, जबकि पिछले चुनाव में पार्टी ने अकेले 215 सीटों हासिल की थी। जबकि भाजपा जिसे पिछले चुनाव में मात्र 77 सीटें मिली थी, उसने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 207 सीटों पर कब्जा जमाया है।

बंगाल में नई विधानसभा गठन की अधिसूचना जारी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में नई विधानसभा के गठन को लेकर चुनाव आयोगने अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे राज्य में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। यह अधिसूचना राज्यपाल को भेज दी गई है, जिसके बाद संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सरकार गठन की आगे की कार्यवाही की जाएगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं विशेषज्ञों का मानना है कि अधिसूचना जारी होना सरकार गठन की दिशा में महत्वपूर्ण संवैधानिक कदम है, जिसके बाद राज्यपाल नई सरकार के गठन के लिए बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को आमंत्रित करेंगे।

असम में 11 मई के बाद बनेगी नई सरकार : हिमंता बिस्वा सरमा

असम,06 मई 2026। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को कहा कि राज्य में नई भाजपा-नीत सरकार का गठन और शपथ ग्रहण समारोह 11 मई के बाद होगा, जब संवैधानिक और संगठनात्मक औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सरमा ने कहा कि चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के नतीजों की औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके बाद उन्होंने लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप अपने मंत्रिपरिषद का इस्तीफा सौंप दिया। सीएम सरमा ने कहा,'चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर नतीजों की घोषणा कर दी है और राज्यपाल को अधिसूचना सौंप दी है। इसके तुरंत बाद, मैंने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया और वर्तमान असम विधानसभा को भंग करने की भी सिफारिश की। 'उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने दोनों सिफारिशें स्वीकार कर लीं और निवर्तमान मंत्रालय से तब तक कार्यवाहक सरकार के रूप में काम जारी रखने को कहा, जब तक कि नया मंत्रालय कार्यभार नहीं संभाल लेता। उन्होंने कहा, 'इस संक्रमण काल के दौरान,जब तक नई सरकार नहीं बन जाती,हम एक कार्यवाहक सरकार के रूप में काम करते रहेंगे। 'हालांकि,सीएम सरमा ने संकेत दिया कि शपथ ग्रहण समारोह 11 मई से पहले नहीं होगा। उन्होंने कहा,'मैंने 12 मई के बारे में चर्चाएं सुनी हैं,हालांकि मैं आधिकारिक तौर पर तारीख की पुष्टि नहीं कर सकता। मैं यह कह सकता हूं कि नई सरकार का गठन और शपथ ग्रहण 11 मई के बाद ही होगा।

राहुल गांधी ने कहा...लोकसभा में भाजपा का हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता

नई दिल्ली,06 मई 2026। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और खासकर ममता बनर्जी की अप्रत्याशित हार ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वोट चोरी का मुद्दा उठाने का मौका दे दिया है। बुधवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल ने हरियाणा की मौजूदा सरकार को घुसपैठ बताया और कहा कि कभी-कभी वोट चोरी से सीटें चुराई जाती हैं तो कभी पूरी सरकार चुराई जाती है। उन्होंने भाजपा के 240 लोकसभा सांसदों में हर छठे सांसद को वोट चोरी से जीता हुआ बताया। राहुल ने एक्स पर लिखा, लोकसभा के 240 भाजपा सांसदों में, मोटे-तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं- क्या उन्हें भाजपा की भाषा में घुसपैठिए कहें? और हरियाणा? वहां तो पूरी सरकार घुसपैठिया है। जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं,मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया को तोड़-मरोड़ते हैं-वो खुद रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। उन्हें असली डर सच्चाई का है। निष्पक्ष चुनाव हों,तो ये 140 के पास भी नहीं जीत सकते। पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम आने के बाद से राहुल लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने एक्स पर लिखा था कि ममता बनर्जी की हार का मजाक बनाने वाले समझ लें कि असम और बंगाल के जनादेश की चोरी, भारतीय लोकतंत्र को तबाह करने के अपने मिशन में भाजपा का एक बड़ा कदम है।

बिहार में आज होगा मंत्रिमंडल का विस्तार

गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह,प्रधानमंत्री सहित कई गणमान्य होंगे शामिल

पटना,06 मई 2026। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार 7 मई को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा। इस शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और इसे लेकर प्रशासनिक व सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जनता जल यूनाइटेड (जदयू) के अध्यक्ष नीतीश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई प्रमुख राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेता शामिल होंगे। कार्यक्रम गुरुवार को दोपहर 12:10 बजे शुरू होगा,जिसमें राज्यपाल नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा से 12, जदयू से 11, लोक जनशक्ति पार्टी-आर से 2 तथा हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (हम)और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) से एक-एक मंत्री शपथ ले सकते हैं। हालांकि, छह पद फिलहाल खाली रखे जाने की संभावना है। बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या के आधार पर मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस अवसर पर पटना दौरे पर रहेंगे। वे न केवल शपथ ग्रहण समारोह में

शामिल होंगे,बल्कि शहर में एक भव्य मेगा रोड शो के जरिए जनता का अभिवादन भी करेंगे। उनके आगमन को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। पटना पुलिस ने समारोह और वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक शहर के कई प्रमुख मार्गों पर सामान्य वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। केवल एंबुलेंस,शव वाहन,आमंत्रित अतिथि और पासधारक वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी। प्रतिबंधित मार्गों में डुमरा टीओपी (शेखपुरा मोड़) से हवाई अड्डा मार्ग,हवाई अड्डा गोलंबर से पटेल गोलंबर,राजेंद्र चौक से पटेल गोलंबर, पटेल गोलंबर से आयकर गोलंबर,चितकोहरा गोलंबर से उत्तर दिशा तथा गर्दनीबाग आरओबी के उत्तर क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा जेपी गोलंबर से डाकबंगला चौराहा और पटना जंक्शन तक सड़क किनारे किसी भी प्रकार की पार्किंग, ठेला या खोमचा लगाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। गांधी मैदान के चारों ओर भी पार्किंग वर्जित रहेगी। आम जनता के लिए गांधी मैदान में प्रवेश गेट संख्या 5,6,7,8,9 और 10 से होगा,जबकि मीडिया के लिए गेट संख्या 11 निर्धारित किया गया है। वाहनों की पार्किंग के लिए जेपी गंगापथ (दीघा गोलंबर से कंगन घाट तक) को चिन्हित किया गया है, जहां बस और चारपहिया वाहन खड़े किए जा सकेंगे। इसके अलावा कृष्णाघाट, पुराने अशोक राजपथ,पटना कॉलेज और पटना साइंस कॉलेज परिसर में भी पार्किंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। पटना पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे जारी ट्रैफिक प्लान का पालन करें और अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित मार्गों पर जाने से बचें। एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी उड़ान से कम से कम तीन घंटे पहले घर से निकलें, ताकि किसी तरह की असुविधा से बचा जा सके। इस भव्य आयोजन को लेकर राजधानी पटना में उत्साह का माहौल है और प्रशासन इसे शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह तैयार है।

चुनाव में भाजपा ने बेईमानी की इसके सैकड़ों वीडियो और शिकायतों के बंडल मेरे पास मौजूद : अखिलेश

लखनऊ,06 मई 2026। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि INDIA गठबंधन लोकसभा चुनाव में आखिरी वक्त तक मजबूती से खड़ा रहा और जीत हासिल की, लेकिन अल्पमत की सरकार बनने के बाद भी विपक्षी दलों के साथ बेईमानी की गई। अखिलेश यादव ने चंडीगढ़ और कुंदरकी सहित विभिन्न स्थानों पर हुई कथित अनियमितताओं को लेकर भाजपा के '10 नम्बरी मॉडल' का जिक्र किया। आरोप लगाया कि भाजपा चुनावी प्रक्रिया में धांधली कर सत्ता बनाए रखने की कोशिश कर रही है। उपचुनाव में 'मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया' का खेलकुंदरकी और रामपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने सबसे तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इन चुनावों में भारी धांधली हुई है। उन्होंने इसे 'मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया' का खेल बताया और आरोप लगाया कि वोटों की डकैती की गई। अखिलेश ने बंगाल हिंसा की निंदा की और सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि बंगाल चुनाव परिणाम पर संज्ञान ले तथा मतगणना लाइव प्रसारित की जाए। उन्होंने कहा कि INDIA गठबंधन बना रहेगा और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने वोट की शर्मनाक लूट की। पुलिस प्रशासन का अवैध इस्तेमाल करने में उसे कतई संकोच नहीं किया। उत्तर प्रदेश में पीडीए की काट भाजपा के पास नहीं है।

बुजुर्ग दंपति समेत 3 की मौत,अपार्टमेंट में जिंदा जले

भुवनेश्वर,06 मई 2026। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बुधवार तड़के एक अपार्टमेंट में भीषण आग लगने से एक ही परिवार के तीन सदस्यों एक बुजुर्ग दंपति और उनकी नाबालिग पोती की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा शहर के लक्ष्मी सागर इलाके स्थित बसंत विला अपार्टमेंट में हुआ। जानकारी के अनुसार, आग सुबह करीब 4 से 4:30 बजे के बीच लगी, जिससे इमारत में तेजी से धुआं फैल गया और वहां रहने वाले लोगों में अफरा-तफरी मच गई। आईएएनएस से बातचीत में भुवनेश्वर के डिप्टी फायर

ऑफिसर नारायण दास ने बताया कि फायर ब्रिगेड को सुबह करीब 5 बजे आग लगने की सूचना मिली। इसके बाद दमकल कर्मी अत्याधुनिक उपकरणों के साथ मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया, जिससे आग को और फैलने से रोका जा सका।

तमिलनाडु में विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया...कांग्रेस ने टीवीके को दिया पूर्ण समर्थन

चेन्नई,06 मई 2026। तमिलनाडु में सरकार के गठन के लिए कांग्रेस के समर्थन के ऐलान के बाद तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) का रास्ता साफ हो गया। बुधवार दोपहर को टीवीके के नेता विजय ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस बार विधानसभा चुनाव के नतीजों से राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव लाया है। तमिलनाडु की जनता ने इस बार एआईएडीएमके और डीएमके को

हासिए पर राज्य की नई पार्टी टीवीके को व्यापक समर्थन दिया, लेकिन किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने से विधानसभा में त्रिशंकु की स्थिति बन गई। ऐसे में राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके को कांग्रेस ने समर्थन देकर गठबंधन सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया। नए घटनाक्रम में टीवीके नेता विजय ने आज राज्यभवन पहुंच कर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने विजय को शॉल ओढ़ाकर बधाई दी और स्मृति चिन्ह भेंट किया।

इसके बाद विजय ने सरकार बनाने के लिए आमंत्रण देने का अनुरोध किया और समर्थन दे रहे विधायकों के पत्र भी राज्यपाल को सौंपे। राज्यपाल से मुलाकात के समय टीवीके के नेता पुस्सी आनंद, सेंगोट्टैयन और आदव अर्जुना भी मौजूद थे।

भारत और वियतनाम ने 13 समझौतों पर किए हस्ताक्षर....

भारत-वियतनाम साथ चलेंगे,साथ बढ़ेंगे,साथ जीतेंगे : पीएम मोदी

नई दिल्ली,06 मई 2026। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत और वियतनाम के संबंध अब बेहतर व्यापक रणनीतिक साझेदारी के नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं और दोनों देश मिलकर विकास और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा,'हम साथ चलेंगे, साथ बढ़ेंगे, और साथ जीतेंगे। ' भारत और वियतनाम ने 13 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच बुधवार को हुई उच्चस्तरीय वार्ता के बाद भारत और वियतनाम ने अपने संबंधों को बेहतर व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा की। दोनों देशों ने व्यापार, रक्षा, कनेक्टिविटी और रणनीतिक सहयोग को नई गति देने का संकल्प संकल्प भी लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में कहा कि राष्ट्रपति तो लाम का भारत दौरा दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों और आपसी प्राथमिकता को दर्शाता है। उन्होंने बताया

कि यह साझेदारी अब और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत-वियतनाम के बीच व्यापार पिछले दशक में दोगुना होकर 16 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अब दोनों देशों ने इसे 2030 तक 25 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य तय किया है। दवाओं, कृषि, मत्स्य और पशु उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई समझौतों पर सहमति बनी है। बहुत जल्द, वियतनाम भारत के अंगूर और अनार का और हम वियतनाम के डूरियन और पोमेलो का स्वाद लेंगे। दोनों देशों ने वित्तीय सहयोग बढ़ाने के तहत भारत के यूपीआई और वियतनाम के फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ने पर सहमति जताई। साथ ही एयर कनेक्टिविटी, स्टेट-टू-स्टेट और सिटी-टू- सिटी सहयोग को भी बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और विजन महासागर का एक मुख्य स्तंभ है। दोनों देशों ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और नियम-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया।

दोनों देशों के बीच समझौतों पर हस्ताक्षर

- आईआरईएल लिमिटेड और वियतनाम के इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी ऑफ रेडियोएक्टिव एंड रेयर एलिमेंट्स के बीच आपसी सहयोग पर समझौता।
- भारत के संस्कृति मंत्रालय और वियतनाम के संस्कृति, खेल और पर्यटन मंत्रालय के बीच 2026-30 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम।
- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और वियतनाम के स्टेट बैंक (एसबीवी) के बीच भुगतान प्रणालियों और डिजिटल भुगतान में नवाचार के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता।
- भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और वियतनाम के स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत औषधि प्रशासन के बीच चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता।
- मुंबई के बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) और हो ची मिन्ह सिटी पीपल्स कमेटी के बीच मित्रता और सहयोग बढ़ाने पर समझौता।
- आईसीसीआर और यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड एजुकेशन (दा नांग विश्वविद्यालय) के बीच 'आईसीसीआर चेयर ऑफ इंडिया स्टडीज' की स्थापना पर समझौता।
- राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय और हनोई स्थित हो ची मिन्ह नेशनल एकेडमी ऑफ पॉलिटिक्स (एचसीएमए) के बीच समझौता।

संपादकीय

फिर खुली फर्जी सेक्युलरिज्म की पोल

पांच राज्यों के चुनावों में से राहुल गांधी को असम और बंगाल के चुनाव नतीजे स्वीकार नहीं हैं। उनके शब्दों में,असम और पश्चिम बंगाल ऐसे स्पष्ट उदाहरण हैं,जहां भाजपा ने चुनाव आयोग के समर्थन से चुनाव चुराया है। हम ममता बनर्जी से सहमत हैं कि बंगाल में सौ से ज्यादा सीटें चुराई गईं। हमने पहले भी मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और 2024 के लोकसभा चुनाव में यह तरीका देखा है। चुनाव चोरी,संस्था चोरी-अब और चारा ही क्या है।

आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने केरलम,तमिलनाडु और पुडुचेरी के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा। केरलम के बारे में तो कह भी नहीं सकते थे,क्योंकि यहां कांग्रेस के नेतृत्व वाले मोर्चे ने जीत हासिल की है। चुनाव नतीजों के बाद उन्होंने तमिलनाडु में शानदार जीत हासिल करने वाले टीवीके प्रमुख जोसेफ विजय को बधाई दी तो पराजय का सामना करने वाले स्टालिन से भी बात की।

ज्ञात हो स्टालिन ने चुनाव नतीजों को सहजता से स्वीकार कर लिया है। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से भी बात की और अपनी एक्स पोस्ट में कांग्रेस के उन लोगों को संभलने की सलाह दी,जो टीएमसी की हार पर खुशी मना रहे। यह वही राहुल गांधी हैं,जिन्होंने बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के ठीक पहले ममता को निशाने पर लेते हुए कहा था कि बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर टीएमसी में कोई न कोई रिश्तेदारी होनी चाहिए,नहीं तो फिर काम नहीं मिलने वाला। ममता पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों और अपनी पार्टी के लोगों के लिए करती हैं और जनता की कोई भी मदद नहीं करतीं। उन्होंने यह भी कहा था,बंगाल में आज लोकतंत्र नहीं,टीएमसी का गुंडाराज चल रहा है।

आखिर राहुल अपनी ही बातों को इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं? माना कि नेताओं की याददाश्त कुछ कमजोर होती है,पर कोई 10-12 दिन पहले की अपनी बातों को कैसे भूल सकता है? राहुल ने बंगाल में प्रचार के दौरान ही ममता को लेकर यह भी कहा था कि बंगाल में बढ़ते ध्रुवीकरण की वजह से ही भाजपा को मौका मिला। इससे इन्कार नहीं कि बंगाल में भाजपा की जीत के कई कारणों में से एक मतदाताओं का ध्रुवीकरण भी रहा। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पर्याप्त कारण हैं कि भाजपा के पक्ष में बड़ी संख्या में हिंदू मतदाता गोलबंद हुए और इसलिए भी उसे बंपर जीत मिली,पर ऐसा केवल इसलिए नहीं हुआ कि भाजपा हिंदुत्व की राजनीति करती है। ऐसा इसलिए भी हुआ, क्योंकि कांग्रेस और तृणमूल सरीखे दल कथित सेक्युलरिज्म के नाम पर मुस्लिम वोटों को गोलबंद करने का काम करते हैं। वास्तव में यह काम खुद को सेक्युलर बताने वाले अधिकतर दल करते हैं। कांग्रेस देश भर में यही करती है और बंगाल में ममता भी यही कर रही थीं और इतना खुलकर कर रही थीं कि वह मुस्लिम तुष्टीकरण में बदल गया।

आम तौर पर मुस्लिम किसी दल के पक्ष में थोक वोट करते हैं और जबसे भाजपा का उभार हुआ है,तबसे वे खास तौर पर उस दल के पक्ष में वोट करते हैं, जो उसे हरा सकने में सक्षम दिखता है। इसके चलते कथित सेक्युलर दल उनकी गोलबंदी में अतिरिक्त परिश्रम करने लगे। वे उनके सामने भाजपा का हौवा खड़ा करते और उनका काम आसान हो जाता। मुस्लिम वोटों की इस गोलबंदी को ध्रुवीकरण के बजाय सेक्युलर राजनीति की संज्ञा दी जाने लगी।

इस फर्जी सेक्युलर राजनीति के चलते एक समय ऐसा आया कि भाजपा विरोधी दलों के लिए मुस्लिम वोट एक तरह के वीटो पावर बन गए। जब भाजपा ने मुस्लिम वोटों को एकजुट करने के जवाब में हिंदू वोटों को गोलबंदी करनी शुरू की तो उसके विरोधियों ने उस पर ध्रुवीकरण की सांप्रदायिक राजनीति करने ठप्पा लगाना शुरू किया। भाजपा ने इस ठप्पे की परवाह न करते हुए सेक्युलरिज्म को छद्म सेक्युलरिज्म की संज्ञा दी और वह उस पर इसलिए बुरी तरह चिपक गया, क्योंकि यही सच था।

निःसंदेह बंगाल में मुस्लिम वोटों के बंटवारे के कारण भी टीएमसी को नुकसान हुआ, लेकिन यदि ममता मुस्लिम समुदाय का इतना खुला तुष्टीकरण नहीं करतीं तो हिंदू भाजपा के पक्ष में खुलकर गोलबंद नहीं होते। ममता केवल इसलिए नहीं हारीं, क्योंकि मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो गया और अधिसंख्य हिंदू वोट भाजपा के खाते में चले गए। वे इसलिए भी हारीं, क्योंकि उनका शासन पक्षपात और उनके नेताओं के भ्रष्टाचार संग उनकी गुंडागर्दी का पर्याय बन गया था। महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी राज्य में महिला असुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा बना। ममता को घुसपैठियों की अनदेखी और मुस्लिमपरस्ती की भी कीमत चुकानी पड़ी। यही कीमत असम में कांग्रेस ने चुकाई। इस पर गौर करें कि असम में एक समय कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ने वाले बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस को आज की मुस्लिम लीग बता दिया। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन अब यह फ्राड बंद होना चाहिए कि मुसलमानों की गोलबंदी तो सेक्युलर राजनीति है और उसके जवाब में हिंदुओं को एकजुट करना सांप्रदायिक राजनीति। मुस्लिम वोटों ने असम और बंगाल में भी अपना वीटो पवार खो दिया और यह मिथ्या धारणा ध्वस्त हो गई कि उनके वोट किसी दल की चुनावी नैया पार लगा सकते हैं,क्योंकि उनका ध्रुवीकरण रिवर्स ध्रुवीकरण करता है।

जनादेश के बाद भी असहमतिः ममता की रणनीति या जिद?

प्रो.आर.के.जैन 'अरिजीत'
बड़वानी,मध्यप्रदेश

लोकतंत्र की कसौटी पर बंगालः जनादेश बनाम व्यक्तिवाद

जनता का आदेश बनाम राजनीतिक अड़ियलपनः बंगाल में बढ़ता संकट

पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव के नतीजों ने न केवल 15 साल पुरानी तृणमूल कांग्रेस की सत्ता का अंत किया, बल्कि गंभीर संवैधानिक टकराव की भूमिका भी बना दी है। भाजपा ने 293 सीटों के नतीजों के अनुसार 294 सदस्यीय सदन में 207 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत पाया, जबकि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सिर्फ 80 सीटों पर सिमट गई। ममता बनर्जी ने परिणामों को 'साजिश' और 'जनादेश की लूट'बताते हुए इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। उनका बयान मैं हारी नहीं,इसलिए राजभवन नहीं जाऊंगी बंगाल की राजनीति को नए मोड़ पर ले गया है। ममता बनर्जी खुद भवानीपुर सीट पर शुभेंदु अधिकारी से हारी हैं। 92.93 प्रतिशत के उच्च मतदान के बावजूद उनका इनकार लोकतंत्र की मूल भावना–जनता के निर्णय–को चुनौती देता है। यह हालात राज्य में अस्थिरता, हिंसा और प्रशासनिक संकट की आशंका बढ़ा रहे हैं।

ममता बनर्जी का रुख चुनावी नतीजों को सीधी चुनौती देता है–यह हार स्वीकार न करने का संकेत है। उन्होंने 100 से अधिक सीटों में धांधली, चुनाव आयोग पर पक्षपात और अपनी नैतिक जीत का दावा किया। ममता ने कहा कि असली लड़ाई भाजपा नहीं,बल्कि चुनाव आयोग से थी। हालांकि,आयोग ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बताते हुए वोटर लिस्ट संशोधन सहित हर कदम का बचाव किया। ममता का 'राजभवन नहीं जाऊंगी' बयान न केवल राज्यपाल के संवैधानिक अधिकारों की अवमानना है, बल्कि शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की लोकतांत्रिक परंपरा को भी आघात पहुंचाता है। जब जनता स्पष्ट जनादेश दे चुकी हो, तब सत्ता से चिपके रहना लोकतंत्र की भावना के विपरीत है। बंगाल में पहले से मौजूद ध्रुवीकरण और पोस्ट-पोल हिंसा इस टकराव से और तीव्र हो सकती है।

संवैधानिक प्रावधान इस विवाद के केंद्र में हैं। अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल राज्यपाल की 'प्रसन्नता' पर पद धारण करते हैं। बहुमत खोने पर राज्यपाल इस्तीफा मांग सकते हैं या फ्लोर टेस्ट करवा सकते हैं। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार की विश्वसनीयता का परीक्षण सदन के फ्लोर पर ही होगा, न कि गवर्नर की निजी राय पर। यदि ममता इस्तीफा नहीं देतीं, तो राज्यपाल विशेष सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट का आदेश दे सकते हैं। 207 बनाम 80 के आंकड़ों में फ्लोर टेस्ट में टीएमसी के लिए बहुमत साबित करना असंभव है। इसके बाद मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना या बर्खास्त होना पड़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, राज्यपाल का यह अधिकार स्पष्ट है और इसे मनमानी नहीं कहा जाएगा।

यदि ममता फ्लोर टेस्ट से बचने या सदन की कार्यवाही से लगातार इनकार करती हैं,तो राज्यपाल के पास बर्खास्तगी और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने का संवैधानिक विकल्प भी उपलब्ध हो जाता है। कई पूर्व सॉलिसिटर जनरल और संवैधानिक विशेषज्ञ मानते हैं कि बहुमत खोकर भी सत्ता में बने रहना संवैधानिक तंत्र के पूर्ण विफल होने का स्पष्ट संकेत है। इतिहास में महाराष्ट्र,कर्नाटक और अन्य राज्यों में ऐसी परिस्थितियां कई बार सामने आई हैं,जहां राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट अनिवार्य कराया या सरकार को बर्खास्त किया। ममता के मामले में भी यही स्थापित संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई जा सकती है,ताकि लोकतंत्र और सुशासन की रक्षा प्रभावी रूप से सुनिश्चित हो सके।

इस टकराव के राजनीतिक और सामाजिक आयाम अत्यंत गहरे और व्यापक हैं। ममता ने इंडिया गठबंधन से समर्थन मांगा और केंद्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं,भाजपा नई सरकार बनाने की सक्रिय और निर्णायक तैयारी में है। यह बदलाव 1937 के बाद बंगाल में पहली दक्षिणपंथी सरकार के उदय का संकेत है। टीएमसी शासन के दौरान भ्रष्टाचार,संदेशखाली जैसी घटनाएं, आरजी कर कांड, हिंसा और प्रशासनिक लापरवाही के आरोपों ने मतदाताओं को भाजपा की ओर निर्णायक रूप से मोड़ा। ममता का इनकार न केवल सत्ता के लोभ और व्यक्तिवाद को उजागर करता है,बल्कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की परंपरा को भी गंभीर चुनौती देता है। पोस्ट-पोल तनाव और कार्यालय तोड़फोड़ की बढ़ती घटनाएं स्थिति को और अधिक जटिल बना रही हैं।

संभावित परिणाम और चुनौतियां अनेक,जटिल और दूरगामी हैं। राज्यपाल यदि शीघ्र और निर्णायक कार्रवाई करते हैं तो बंगाल में अल्पकालिक राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है,जिसके बाद नई सरकार का गठन संभव होगा। लेकिन इससे कानून-व्यवस्था बिगड़ने और व्यापक विरोध प्रदर्शनों के उभरने की आशंका और प्रबल होगी। दूसरी ओर,यदि ममता अदालत का रुख करती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट बोम्मई फैसले के आधार पर त्वरित फ्लोर टेस्ट का आदेश दे सकता है। यह पूरा प्रकरण भारत की संघीय व्यवस्था की वास्तविक मजबूती और संतुलन की गंभीर परीक्षा भी है। केंद्र-राज्य संबंधों में संतुलन बनाए रखना और लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रभावी रक्षा करना अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य है।

जब संस्थाएं और जनादेश आमने-सामने खड़े हों,तब लोकतंत्र की असली कसौटी सामने आती है–बंगाल आज उसी मोड़ पर है। जनादेश सर्वोपरि होता है और हर नेता को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ऊपर उठकर उसे स्वीकार करना चाहिए–यही सच्ची और परिपक्व लोकतांत्रिक परंपरा है। ममता बनर्जी को अब सदन में बहुमत साबित करने का अवसर मिलना चाहिए या शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरण करना चाहिए। राज्यपाल,चुनाव आयोग और न्यायपालिका संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप समाधान निकालेंगे। इससे बंगाल में स्थिर और प्रभावी सरकार बनेगी तथा विकास की नई राह खुलेगी। यह टकराव ममता बनाम राज्यपाल से आगे बढ़कर लोकतंत्र बनाम व्यक्तिवाद का व्यापक प्रश्न बन गया है। शांतिपूर्ण और संवैधानिक समाधान ही बंगाल की जनता की सर्वोच्च अपेक्षा है।

प्रकृति के व्यवहार नहीं हमर व्यवहार बदले हावय

लक्ष्मीनारायण सेन
गरियाबंद,छत्तीसगढ़

जेठ के महिना हा गर्मी के महिना आए,जेनमा धुर्रा उड़ाते अउ बासी हा गजब सुहाते,फेर प्रकृति के रचना हा घलो उटपटांग आए अभी धुर्रा के जगा मा चिख्ला होवत हे अउ शरबत के जगा मा चाय हा सुहावत हे। सावन भादो कस गली खोर मा पानी बोहावत हे। लइका धुर्रा के जगा मा चिख्ला ला छपछपावत हे। आदमी हा अपन करम मा परदा डारत हे अउ प्रकृति ला अड़बड़ कोसत हे। हे भगवान यहा गर्मी के दिन मा बरसात कस पानी बरसावत हस,जम्मो के काम बुता ला तँय बिगाड़त हस। प्रकृति के स्वभाव के अन्तर्गत जब मौसम बदलते,ता हमन प्रकृति ला अड़बड़ चिल्लाथन,पर हमन एको नइ सोचन कि काबर मौसम हा बदलत हे,अउ बेमौसम बरसात आए दिन पानी हा काबर गिरत हे।

प्रकृति मा मौसम के बदलाव अउ प्रकृति के

ऋतु के उल्टा व्यवहार मा प्रकृति के एको दोष नइ हे। हम मइन्शे के सुवारथ अउ प्रकृति के नियम के उल्टा हमर काम हरे।हमन गली खोर मा चिख्ला झन होए कहिके गली के संग संग भांठा ला घलो कांकरेटिकरण कर देत हन।जंगल,खेत खार भांठा के रुखराई अउ खेत के पैराली ला हमन जलावत हन। रूखराई ला आए दिन अपन सुवारथ बर काटत हन। यहां तक के हमन जेन ला गौ माता कथन ओकर संग मा हमन खेल खेलत हन गौ माता संग प्रकृति ला छोड़ बनावटी गरभधान ला हमन अपनावत हन।अपन सुवारथ खातिर अइशने कइयों ठन बुता ला हमन प्रकृति के नियम के उल्टा करत हन,ता हम जम्मो झन ला प्रकृति के प्रकोप तो सहे ला लागही। प्रकृति हा अपन जगा मा जइसन हावय उसने अभी भी हावय। बदले हावय तो हमर सुवारथ के सीमा बढ़ें हावय। हमन केवल अपन बारे मा ही सोचतन अउ प्रकृति के नियम के उल्टा हमन व्यवहार करतन,अउ प्रकृति ला दोष देत हन जेन हा हमर गलती आए।

हमर सियानन मन भले कम पढ़ें लिखे रिहीश पर प्रकृति के संग घुल-मिल के रहय अउ प्रकृति ला सजाए बर कोनो कसर नइ छोड़य। जेकर सेति उकर मन के समय मा जाड़ गर्मी अउ बरसात हा एक बरोबर रहय अउ सहज रूप ले प्रकृति के संग अपन आप ला ढाल लेवय अउ मौसम बदलाव के संग कोनो किस्म के बीमार के शिकार नइ होवय।

समय

मोनिका डागा आनंद,
चेन्नई,तमिलनाडु

हर पल बड़ा,बलवान है, सबका समय,भगवान है।
मेहनत से,मुस्कान है,सुंदर बने,दिनमान है।।

हिम्मत कर,विश्वास रख,मेहनत का,परिणाम चख।
रख हौसला,पाले विजय,कर साधना,हो दिग्विजय।।

छू ले गगन,सपना सजा,श्रम गीत गा,बाजा बजा।
सीढ़ी बना,विस्तार दे,नूतन सपन,आकार दे।।

सम्मान कर,तू काल का,चलते समय,गतिमान का।
थमता नहीं,डरना नहीं, बाधा कहीं,मुश्किल कहीं।।

राही कदम,रखना सही,मंज़िल मिले,इच्छित वही।
हर पल यहाँ,तो दौड़ हैं,सुख-दुख समय,का जोड़ हैं।।

कमजोर क्यूँ,इतना बना,तू है निडर,उर को मना।
होगी विजय,इस प्यास की,आत्मिक सुखद,विश्वास की।।

जगती सदा,आशा वहीं,जो धैर्य को,छोड़े नहीं।
तू समझ लें,इस बात को,पा सुखद सी,सौगात को।।

बीता समय,वापस कभी,आता नहीं,रोते सभी।
मौका मिले,कल हॉ नहीं,चिंता सदा,रहती वहीं।।

राहें बने,व्यहवार से,स्वीकृति सहज,स्वीकार से ।
आगे निकल,छोड़कर दुख,आनंद भर,जीतकर सुख।।

तू मत बिखर,कर प्यार कुछ,करता समय,ही कुछ न कुछ।
भीतर जगा,उस चाह को,तू सीख जा, उस वाह को।।

गतिमय समय,पल-पल घटे,खुश हो चला,संकट छटे।
कीमत समझ,कर जो चलें, शुभ ही सदा,प्रतिफल मिलें ।

योग का उद्भव और सॉफ्ट पावर

डॉ. सत्यवान सौरभ
बड़वा भिवानी, हरियाणा

योग एक प्राचीन भारतीय अनुशासन से विकसित होकर भारत की सॉफ्ट पावर के एक शक्तिशाली साधन के रूप में उभरा है। यह कथन न केवल योग की ऐतिहासिक यात्रा को रेखांकित करता है, बल्कि समकालीन वैश्विक परिदृश्य में सांस्कृतिक कूटनीति की भूमिका को भी उजागर करता है, विशेषकर एक तेजी से विभाजित होती दुनिया में जहां वैश्विक विश्वास और सामाजिक एकजुटता की कमी गंभीर चुनौती बन चुकी है। योग की उत्पत्ति सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेषों से लेकर उपनिषदों और पतंजलि के योगसूत्र तक जाती है, जहां इसे मन, शरीर और आत्मा के समन्वय का विज्ञान माना गया। प्राचीन काल में योग आध्यात्मिक साधना का माध्यम था, लेकिन आधुनिक युग में यह शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और जीवनशैली का अभिन्न अंग बन गया। स्वामी विवेकानंद ने 1893 के शिकागो धर्म संसद में योग को पश्चिमी दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे इसकी वैश्विक स्वीकार्यता की नींव पड़ी। फिर भी, वास्तविक परिवर्तन तब आया जब 21 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया, जिसके पीछे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्ताव था। इस निर्णय ने योग को मात्र एक व्यायाम न बनाकर सांस्कृतिक राजदूत का रूप प्रदान किया। आज योग 190 से अधिक देशों में मनाया जाता है, जो भारत की सॉफ्ट पावर को प्रमाणित करता है। सॉफ्ट पावर, जो जोसेफ नाई ने परिभाषित की, आकर्षण और प्रभाव के माध्यम से प्रभाव डालने की क्षमता है, न कि बल प्रयोग से। भारत के संदर्भ में योग इसकी परिपूर्ण अभिव्यक्ति है, क्योंकि यह बिना किसी विवाद के वैश्विक स्तर पर अपनाया गया। उदाहरणस्वरूप, संयुक्त राज्य अमेरिका में योग उद्योग 16 बिलियन डॉलर का है, जबकि यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में यह स्वास्थ्य नीतियों का हिस्सा बन चुका है। यह न केवल आर्थिक लाभ प्रदान करता है, बल्कि भारत की छवि को शांतिप्रिय, समावेशी और प्राचीन ज्ञान का भंडार के रूप में स्थापित करता है।

सांस्कृतिक कूटनीति सॉफ्ट पावर का मूल आधार है, जो राज्य और समाज के बीच पुल का कार्य करती है। यह कूटनीति पारंपरिक राजनयिक वार्ताओं से परे जाती है और संस्कृति, कला, संगीत, नृत्य तथा जीवन दर्शन के माध्यम से संबंधों को गहरा करती है। एक तेजी से विभाजित दुनिया में, जहां भू-राजनीतिक तनाव जैसे रूस-यूक्रेन संघर्ष, अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध, मध्य पूर्व की अस्थिरता और घरेलू स्तर पर ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, सांस्कृतिक कूटनीति एकमात्र ऐसा माध्यम है जो वैचारिक सीमाओं को पार कर सकता है। वैश्विक विश्वास का संकट आज चरम पर है। प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वेक्षण बताते हैं कि बहुसंख्यक देशों में अंतरराष्ट्रीय संस्थानों पर भरोसा घटा है, जबकि

सोशल मीडिया जनित फेक न्यूज ने विभाजन को और गहरा किया है। ऐसे में सांस्कृतिक कूटनीति साझा मानवीय मूल्यों को पुनर्स्थापित करती है। योग इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजनों में विविध संस्कृतियों के लोग एक साथ आसन करते हैं, जो सामाजिक एकजुटता का प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रमों से लेकर टाइम्स स्क्वायर की सड़कों तक, योग ने विभाजित समाजों को जोड़ा है। भारत ने इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के माध्यम से योग केंद्र स्थापित किए हैं, जो न केवल प्रशिक्षण देते हैं बल्कि सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करते हैं। नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में योग ने ऐतिहासिक बंधनों को मजबूत किया, जबकि यूरोपीय संघ के देशों में यह तनावग्रस्त जीवनशैली के समाधान के रूप में लोकप्रिय हुआ। योग की सफलता सांस्कृतिक कूटनीति के तीन प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है: समावेशिता, सार्वभौमिकता और दीर्घकालिक प्रभाव। समावेशिता इसलिए क्योंकि योग किसी धर्म या जाति से बंधा नहीं;यह हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी के लिए है। अमेरिका में अफ्रीकी-अमेरिकी समुदायों ने योग को सामाजिक न्याय आंदोलन से जोड़ा, जबकि मध्य पूर्व के मुस्लिम देशों में इसे इस्लामी ध्यान प्रक्रियाओं के साथ संयोजित किया गया। सार्वभौमिकता योग के दर्शन में निहित है **वसुधैव कुटुंबकम**। यह संदेश कोविड-19 महामारी के दौरान विशेष रूप से प्रासंगिक साबित हुआ,जब भारत ने योग फॉर वेलनेस अभियान चलाकर वैश्विक स्वास्थ्य संकट से जूझते देशों को जोड़ा। ऑनलाइन योग सत्रों ने लाखों लोगों को घरों तक पहुंचाया, जो सांस्कृतिक कूटनीति का डिजिटल रूप था। दीर्घकालिक प्रभाव योग के माध्यम से युवा पीढ़ी पर पड़ता है। विश्वविद्यालयों में योग कोर्सेस,स्कूलों में पाठ्यक्रम और कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम्स ने इसे जीवन का हिस्सा बना दिया। फ्रांस में यूनेस्को की मान्यता प्राप्त योग संस्थान और जर्मनी के योग महोत्सव इसका प्रमाण हैं। ये प्रयास न केवल विश्वास निर्माण करते हैं बल्कि सामाजिक एकजुटता को भी बढ़ाते हैं। विभाजित दुनिया में, जहां आर्थिक राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक अलगाव बढ़ रहा है, योग जैसे तत्व सहिष्णुता सिखाते हैं। उदाहरण के लिए,इजरायल-फिलिस्तीन तनाव के बीच तेल अवीव में आयोजित योग सत्रों ने शांति का संदेश दिया। इसी प्रकार, अफ्रीकी देशों में योग ने गरीबी और स्वास्थ्य असमानताओं से निपटने में सहायता की।

भारत की सॉफ्ट पावर रणनीति में योग केंद्रीय है। पिछले दशक में भारत ने सॉफ्ट पावर इंडेक्स में अपनी रैंकिंग सुधारी है, जहां योग, आयुर्वेद और बॉलीवुड प्रमुख घटक हैं। जी-20 शिखर सम्मेलनों में योग सत्रों ने मेजबान देशों को प्रभावित किया। 2023 के दिल्ली जी-20 में अफ्रीकी संघ की सदस्यता के साथ योग ने वैश्विक दक्षिण को एकजुट किया। सांस्कृतिक कूटनीति ने भारत को विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित किया। ब्रिटिश काउंसिल और गोएथे इंस्टीट्यूट जैसे पश्चिमी मॉडल्स के विपरीत,भारत का मॉडल अधिक समग्र है। मिशन सूर्योदय जैसे कार्यक्रमों ने 100 देशों में सूर्य नमस्कार को प्रोत्साहित किया, जो पर्यावरणीय जागरूकता से जुड़ा। यह प्रयास जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों पर एकजुटता दिखाते हैं। हालांकि चुनौतियां हैं वाणिज्यीकरण से योग का आध्यात्मिक स्वरूप कमजोर हो रहा है, पश्चिमी अनुकूलन में मूल तत्व खो रहे हैं। फिर भी,भारत सरकार की नीतियां जैसे आयुष मंत्रालय और मंत्रालय ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के संयुक्त प्रयास इनका समाधान कर रहे हैं। तेजी से विभाजित दुनिया में सांस्कृतिक कूटनीति की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के बाद ध्रुवीकरण,यूरोपीय संघ की आंतरिक दरारें और एशिया में सीमा विवादों ने विश्व को खंडित किया है।

बहुत कुछ.

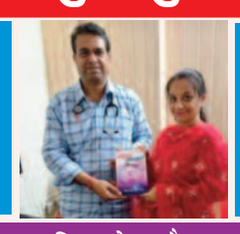

गरिमा राकेश गौत्तम
राजस्थान

बहुत कुछ बोलने के पश्चात
बहुत कुछ शेष रह जाता है
ये बहुत कुछ शेष ही
बहुत उदासी का कारण बन जाता है ।
बहुत कुछ देख कर भी
बहुत कुछ अनदेखा रह जाता है
ये जो बहुत अनदेखा है
ये अंतर्मन में देखा जा सकता है ।
बहुत चलने के पश्चात भी
बहुत कुछ चलना शेष रह जाता है
ये जो शेष रह जाता है
कही मन की छाँव में डेरा डाल जाता है ।
बहुत कुछ पाकर भी
जब बहुत कुछ छूट जाता है
ये छूटा बहुत कुछ ही
ईश्वर की राह ले जाता है ।
बहुत कुछ की परिभाषा में
बहुत कुछ आता -जाता हैं
इस बहुत कुछ में
थोड़ी सी आशा
थोड़ी सी मेहनत
थोड़ा सा धैर्य
थोड़ा सा साहस
बहुत बहुत बहुत...कुछ दिला जाता है ।

सूचना
समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
-सम्पादक

CMYK

सरगुजा संभाग में प्रशासनिक महा फेरबदल...कोरिया से बलरामपुर पहुंचीं चंदन त्रिपाठी,पुष्पा साहू को मिला जिला,MCB की कमान संतन देवी जांगड़े के हाथ

-न्यूज डेस्क-

रायपुर/अंबिकापुर/कोरिया,06 मई 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ शासन ने एक बार फिर बड़े प्रशासनिक फेरबदल के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार अब जिलों की कार्यशैली,योजनाओं की रफ्तार और जमीनी मॉनिटरिंग को लेकर नए समीकरण तैयार कर रही है,सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी तबादला आदेश में कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के प्रभार बदले गए,लेकिन सरगुजा संभाग में हुआ बदलाव सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया हैं।

सरगुजा संभाग के तीन महत्वपूर्ण जिलों कोरिया,बलरामपुर और मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में कलेक्टर स्तर पर बदलाव किया गया है,शासन ने कोरिया कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी को बलरामपुर-रामानुजगंज का नया कलेक्टर बनाया है,वहीं लंबे समय से जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी का इंतजार कर रहीं आईएएस अधिकारी पुष्पा साहू को कोरिया जिले की कमान सौंपी गई है, इसके साथ ही एमसीबी जिले में पूर्व जिला पंचायत सीईओ रहीं संतन देवी जांगड़े को नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है,इन बदलावों ने प्रशासनिक गलियारों के साथ-साथ राजनीतिक हलकों में भी चर्चाओं का दौर तेज कर दिया है।

आखिरकार पुष्पा साहू को मिला जिला

इस फेरबदल की सबसे बड़ी चर्चाओं में से एक नाम आईएएस अधिकारी पुष्पा साहू का रहा,लंबे समय से प्रशासनिक हलकों में यह चर्चा थी कि उन्हें जल्द किसी जिले की जिम्मेदारी मिल सकती है,अब शासन ने उन्हें कोरिया जिले का नया कलेक्टर बनाकर यह संकेत दे दिया है कि सरकार नए चेहरों को फील्ड में मौका देने के मूड में है, पुष्पा साहू इससे पहले विभिन्न प्रशासनिक विभागों में जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं, लेकिन जिला कलेक्टर की भूमिका हमेशा प्रशासनिक क्षमता की असली परीक्षा मानी जाती है, कोरिया जैसे सीमावर्ती और संसाधन आधारित जिले में उनकी कार्यशैली पर अब सभी की नजर रहेगी,कोरिया जिले में खनिज,वन,राजस्व,सड़क,स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े कई मुद्दे लंबे समय से चर्चा में रहे हैं,इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और प्रशासनिक निगरानी को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं,ऐसे में नए कलेक्टर के सामने चुनौतियां कम नहीं होंगी।

कोरिया से विदाई...अब बलरामपुर की जिम्मेदारी...

कोरिया जिले की कलेक्टर रहीं चंदन संजय त्रिपाठी को अब बलरामपुर जिले की जिम्मेदारी दी गई है,कोरिया में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई प्रशासनिक अभियानों,राजस्व मामलों,जनदर्शन और सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग को लेकर सक्रिय भूमिका निभाई थी,हालांकि उनके कार्यकाल को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आती रहीं,एक वर्ग उन्हें शांत और व्यवस्थित प्रशासनिक अधिकारी मानता रहा,तो वहीं कई मामलों में स्थानीय स्तर पर धीमी प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर सवाल भी उठे,इसके बावजूद शासन ने उन्हें संवेदनशील और सीमावर्ती जिला बलरामपुर की जिम्मेदारी देकर भरोसा जताया है,बलरामपुर जिला कानून व्यवस्था, सीमावर्ती गतिविधियों और आदिवासी अंचल की चुनौतियों के कारण प्रशासनिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, ऐसे में वहां उनका कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रहने वाला है।

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर को मिला नया प्रशासनिक चेहरा

नवगठित जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में भी बड़ा बदलाव किया गया है, शासन ने यहां संतन देवी जांगड़े को नया कलेक्टर नियुक्त किया है, संतन देवी जांगड़े पहले कोरिया जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रह चुकी हैं और क्षेत्र की प्रशासनिक व भौगोलिक परिस्थितियों से अच्छी तरह परिचित मानी जाती हैं, जिला पंचायत में रहते हुए उन्होंने ग्रामीण विकास, पंचायत योजनाओं और जमीनी क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाई थी,यही कारण है कि शासन ने उन्हें मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जैसे नए जिले की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया,मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला अभी प्रशासनिक रूप से पूरी तरह स्थिर नहीं माना जाता। यहां आधारभूत ढांचे, राजस्व व्यवस्था,नगरीय विकास, स्वास्थ्य सुविधाएं और ग्रामीण योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर लगातार काम जारी है। ऐसे में संतन देवी जांगड़े के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रशासनिक संतुलन और विकास की गति बनाए रखने की होगी।

नए अधिकारियों के सामने क्या होंगी चुनौतियां?

कोरिया:-
- स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था में सुधार
- ग्रामीण सड़कों और बुनियादी ढांचे की स्थिति
- राजस्व मामलों का निराकरण
- सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रशासनिक पकड़ मजबूत करना

बलरामपुर:-
- कानून व्यवस्था
- वन एवं आदिवासी क्षेत्रों की समस्याएं
- विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग
- संवेदनशील इलाकों में प्रशासनिक सक्रियता

एमसीबी:-
- नवगठित जिले की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करना
- नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में संतुलित विकास
- स्वास्थ्य और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुधारना
- विभागीय समन्वय को बेहतर बनाना

क्या सिर्फ तबादला या बड़े राजनीतिक संकेत?

सरगुजा संभाग में एक साथ तीन जिलों के कलेक्टर बदलने को केवल नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं माना जा रहा,राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इसे आने वाले समय की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है,माना जा रहा है कि शासन अब जिलों में योजनाओं के क्रियान्वयन,जनसंपर्क और प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर ज्यादा सख्ती के मूड में है, कई जिलों में योजनाओं की धीमी प्रगति, शिकायतों और जमीनी असंतोष को देखते हुए यह फेरबदल किया गया है, कुछ जानकार इसे आगामी राजनीतिक समीकरणों और क्षेत्रीय संतुलन से भी जोड़कर देख रहे हैं, खासकर सरगुजा संभाग, जो हमेशा से राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील माना जाता रहा है, वहां प्रशासनिक बदलावों को सामान्य नजर से नहीं देखा जाता।

जनता की नजर अब कामकाज पर

तबादला आदेश जारी होते ही प्रशासनिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गईं, लेकिन आम जनता की अपेक्षा अब केवल एक ही है— 'जमीन पर काम दिखाई दे, सरगुजा संभाग के कई जिलों में स्वास्थ्य व्यवस्था, सड़क, शिक्षा,पेयजल और राजस्व से जुड़ी समस्याएं लगातार सामने आती रही हैं, ऐसे में नए अधिकारियों से लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं, अब देखना यह होगा कि ये प्रशासनिक बदलाव केवल फाइलों तक सीमित रहते हैं या फिर वास्तव में जिलों की कार्यशैली और विकास की रफ्तार में भी बदलाव नजर आता है।

संत गहिरा विश्वविद्यालय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर कार्यशाला शुरू

विशेषज्ञों ने छात्रों को एआई के उपयोग व नई तकनीकों की दी जानकारी

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,06 मई 2026 (घटती-घटना)।

संत गहिरा विश्वविद्यालय, सरगुजा में पांच दिवसीय कार्यशाला कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पर व्यवहारिक प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला के तहत विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान और प्रायोगिक सत्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक की जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर मुख्य वक्ता डॉ. विवेक कुमार गुप्ता ने विभिन्न एआई उपकरणों के उपयोग पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में शिक्षण और शोध कार्यों के लिए कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपयोगी साबित हो रहे हैं, जिनसे अध्ययन को सरल और प्रभावी बनाया जा सकता है। साथ ही एनीमेशन और शोध कार्यों में एआई

की भूमिका भी तेजी से बढ़ रही है। दूसरे सत्र में डॉ. मनीष देवांगन ने चैटजीपीटी, कैनवा सहित अन्य एआई आधारित प्लेटफॉर्म के उपयोग को समझाया। उन्होंने ऑनलाइन आवेदन, सामग्री निर्माण, धोखाधड़ी की पहचान और सर्च इंजन में एआई के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके बाद डॉ. जया शर्मा ने वीडियो निर्माण, चित्र निर्माण और एनीमेशन से जुड़े विभिन्न एआई टूल्स की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एआई के माध्यम से रचनात्मक कार्यों में नई संभावनाएं विकसित हो रही हैं। अंतिम सत्र में डॉ. अनूप कुमार मिश्रा ने दैनिक जीवन में एआई के उपयोग जैसे स्मार्ट उपकरण, डिजिटल सहायक, चेहरे की पहचान और अन्य तकनीकों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति, प्राध्यापकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. ईश राठौर प्रसाद तिवारी ने किया।

सरगुजा संभाग में कृषि विकास को नई दिशा,एपीसी समीक्षा बैठक में बने बड़े प्लान...

रबी 2025-26 की समीक्षा: खरीफ 2026 की रणनीति तय फसल विविधीकरण,जल संरक्षण और ई-उर्वरक प्रणाली पर जोर

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,06 मई 2026 (घटती-घटना)।

कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती शहला निगार की अध्यक्षता में जिला कलेक्टरेट सभाकक्ष में सरगुजा संभाग स्तरीय एपीसी समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में रबी वर्ष 2025-26 की प्रगति की समीक्षा के साथ खरीफ वर्ष 2026 के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई। बैठक की शुरुआत में सभी जिलों के कलेक्टरों ने रबी सीजन की उपलब्धियों और योजनाओं के क्रियान्वयन पर एजेंडा-वार प्रस्तुतीकरण दिया। इसके बाद विभागीय अधिकारियों ने विभागवार प्रगति रिपोर्ट पेश करते हुए आगामी रणनीति पर चर्चा की।

फसल विविधीकरण पर विशेष जोर

कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि सरगुजा संभाग में कृषि की अपार संभावनाएं हैं, जिनका बेहतर उपयोग करने की जरूरत है। उन्होंने दलहन,तिलहन,प्राकृतिक खेती और उद्यानिकी के माध्यम से फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। किसानों को पारंपरिक धान फसल के साथ अन्य फसलों की ओर प्रेरित करने और धान के रकबे को कम कर वैकल्पिक फसलों का विस्तार करने पर जोर दिया गया।

जल संकट को देखते हुए बदलेगा कृषि एजेंडा

उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ कृषि का एजेंडा भी बदलना जरूरी है। भूजल स्तर में गिरावट और पानी की कमी को देखते हुए जल संरक्षण के उपायों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

पशुपालन,मत्स्य व उद्यानिकी को मिलेगा बढ़ावा

बैठक में पशुपालन, मत्स्य पालन और उद्यानिकी क्षेत्रों में विशेष प्रयास करने की बात कही गई। पशुपालन में चारा उपलब्धता और नस्ल सुधार को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। वहीं नाशपाती, लीची और कटहल जैसे स्थानीय फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के माध्यम से बाजार उपलब्ध कराने पर बल दिया गया।

ई-उर्वरक वितरण प्रणाली होगी लागू : खरीफ 2026 से नई ई-उर्वरक वितरण प्रणाली लागू करने पर चर्चा हुई, जिसके तहत एग्रीस्टेक में दर्ज फसल और रकबे के आधार पर उर्वरकों का वितरण किया जाएगा। आयुक्त ने सभी किसानों का एग्रीस्टेक में पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उर्वरक वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उड़नदस्ता दल गठित करने, विक्रय केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही नकली खाद और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के लिए भी कहा गया।

किसानों को जागरूक करने पर जोर

शिविरों के माध्यम से किसानों को उर्वरकों के सही उपयोग और वैकल्पिक स्त्रोत जैसे हरी खाद, जैव उर्वरक और नील हरित काई के बारे में जानकारी देने के निर्देश दिए गए। बैठक में पीएम किसान योजना के तहत फार्मर आईडी निर्माण, लाभ से वंचित किसानों के पंजीयन, निर्यात योग्य धान की किस्मों के विस्तार तथा विकसित कृषि संकल्प अभियान (खरीफ 2026) के क्रियान्वयन पर भी विस्तार से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

अधिकारियों की रही उपस्थिति

बैठक में सरगुजा संभागायुक्त श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा सहित विभिन्न जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

कोटपा अधिनियम के तहत पान ठेलों पर चालानी कार्रवाई

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,06 मई 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार तथा नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं कलेक्टर सरगुजा के आदेशानुसार जिले में 27 अप्रैल से 11 मई तक ''सही दवा, शुद्ध आहार-यही छत्तीसगढ़ का आधार'' थीम अंतर्गत 15 दिवसीय सघन जांच अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में 06 मई 2026 को सरगुजा जिले में संयुक्त जांच टीम द्वारा पान ठेलों पर कार्रवाई करते हुए कोटपा अधिनियम के तहत 22 पान ठेलों पर चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान कुल 1800 रुपये की चालान राशि वसूल की गई। जांच के दौरान दुकानदारों को तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों के सुरक्षित रख-रखाव एवं धूम्रपान निषेध संबंधी चेतावनी बोर्ड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों का विक्रय नहीं करने हेतु सख्त हिदायत दी गई। यह कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा की गई। जिले में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

खुशनुमा जीवन ही हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य...उमंग समर कैंप में 'खुशी दिवस' मनाया गया

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,06 मई 2026 (घटती-घटना)।

प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए आयोजित उमंग समर कैंप का पांचवा दिन आज खुशी दिवस के रूप में मनाया गया और बच्चों ने आज के लिए सुविचार लिये कि मैं खुशनुमा आत्मा हूं। आज के दिवस का शुभारंभ मेडिटेशन से किया गया। इसके पश्चात ब्रह्माकुमारी विद्या दीदी जी ने खुशनुमा जीवन पर अपने विचार रखते हुए कहा कि खुशनुमा जीवन ही हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। कोई भी बाहरी साधन वस्तु , वैभव या व्यक्ति हमें स्थाई खुशी नहीं दे सकता। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो हमें सच्ची खुशी मिलती है हमारे आंतरिक गुण ही हमको सच्ची खुशी दे सकती है आगे उन्होंने कहा कि बाहरी परिस्थिति हमें दुखी नहीं करती पर हमारा उसके प्रति नजरिया हमें दुख देता है।

खुशहाल जीवन के चार मूल मंत्र :

दृष्टिकोण (एटीट्यूड) : हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखें।

संतुलन (बैलेंस) : शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन जरूरी है।

सहयोग (कोऑपरेशन) : एक-दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ें।

न्यारापन (डिटैचमेंट) : कर्म करें, लेकिन फल की चिंता न करें।

गतिविधियों में दिखा उत्साह : इसके बाद बीके ज्योति बहन ने बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए माइंड जिम गेम्स कराए, जिसमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। साथ ही पेंटिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने दिए गए विषय पर अपनी कल्पनाओं को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया।

बतौली मेन मार्केट में दिनदहाड़े चोरी,1.70 लाख रुपए पार

दुकानदार को बातों में उलझाकर वारदात,सीसीटीवी में कैद हुए आरोपी

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,06 मई 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा जिले के बतौली मेन मार्केट में स्थित एक पतंजलि स्टोर्स में बुधवार को दिनदहाड़े चोरी की घटना सामने आई है। दो युवकों ने दुकानदार को बातों में उलझाकर काउंटर में रखे 1 लाख 70 हजार रुपए पार कर दिए और फरार हो गए। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी के अनुसार, बतौली निवासी रजत गुप्ता की मुख्य बाजार में पतंजलि स्टोर्स है। बुधवार दोपहर करीब सवा 12 बजे उनके पिता संकट मोचन गुप्ता स्टेट बैंक से रुपए निकालकर दुकान पहुंचे थे। उन्होंने पैसे कागज में लपेटकर काउंटर में रखे थे। इसी दौरान 2 युवक दुकान में पहुंचे। एक युवक ने चेहरे पर रुमाल बांध रखा था। दोनों ने तेल खरीदने के बहाने दुकानदार को बातचीत में उलझा लिया। इस बीच एक युवक काउंटर से रुपए निकालकर फरार हो गया, जबकि दूसरा भी कुछ सेकेंड बाद बिना सामान लिए भाग निकला। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई है। फुटेज में दिख रहा है कि एक युवक दुकानदार को दुकान के अलग-अलग हिस्सों में भेजता रहा, जबकि दूसरा युवक काउंटर से रुपए निकालकर भाग गया।

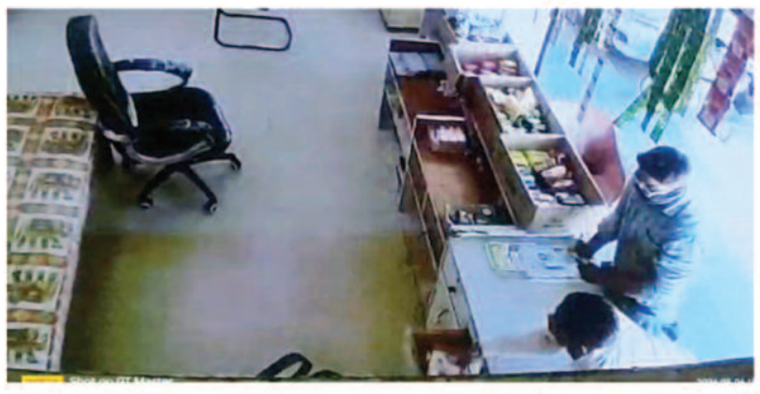

बैंक से ही पीछा करने की आशंका

प्राथमिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि आरोपी बैंक से ही दुकानदार का पीछा कर रहे थे। रास्ते में मौका नहीं मिलने पर उन्होंने दुकान में वारदात को अंजाम दिया।

पुलिस जांच में जुटी

घटना की रिपोर्ट बतौली थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है।

फर्जी दस्तावेज पर नौकरी करने वाला प्रधान पाठक निलंबित

जांच में खुलासा : दस्तावेजों में गड़बड़ी के बाद प्रशासन ने की कार्रवाई,शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप

-संवाददाता-
बलरामपुर,06 मई 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा जिले में शिक्षा विभाग से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे एक प्रधान पाठक पर कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद विभागीय व्यवस्था और नियुक्ति प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार,कोल्हुआ प्राथमिक शाला स्कूल में पदस्थ प्रधान पाठक लालमन सिंह के दस्तावेजों की जांच के दौरान कई विसंगतियां पाई गईं। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि नियुक्ति के समय प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र संदिग्ध थे, जिसके बाद विभाग ने विस्तृत जांच शुरू की।

प्रशासन ने लिया त्वरित निर्णय

मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया। साथ ही विभागीय जांच भी प्रारंभ कर दी गई है, ताकि पूरे मामले की गहराई से जांच कर आगे की वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

जांच में क्या मिला?

जांच अधिकारियों ने पाया कि प्रस्तुत शैक्षणिक एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों में तथ्यात्मक त्रुटियां और संभावित फर्जीवाड़ा शामिल है। दस्तावेजों की सत्यता की पुष्टि के लिए संबंधित बोर्ड/संस्था से भी जानकारी ली गई, जिसमें गड़बड़ी की पुष्टि हुई।

विभाग में मचा हड़कंप : इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। अब अन्य कर्मचारियों के दस्तावेजों की भी जांच किए जाने की चर्चा है। अधिकारियों का कहना है कि यदि कहीं भी फर्जीवाड़ा पाया गया, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नियुक्ति प्रक्रिया पर उठे सवाल

इस पूरे प्रकरण ने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और सत्यापन प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते जांच नहीं होती, तो यह मामला लंबे समय तक दबा रह सकता था।

सबसे बड़ा सवाल

क्या शिक्षा विभाग अब अन्य नियुक्तियों की भी व्यापक जांच करेगा, या यह कार्रवाई केवल एक मामले तक सीमित रह जाएगी?

एनएच-130 पर दो हाईवा की भिड़ंत,चालक फंसा

भीठी के पास हादसा,एक घंटे तक हाईवे बंद रेस्क्यू के बाद ड्राइवर अस्पताल में भर्ती

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,06 मई 2026 (घटती-घटना)।

मणिपुर थाना क्षेत्र के भीठी के पास एनएच-130 पर बुधवार को दो हाईवा वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। जानकारी के अनुसार, एक हाईवा ने दूसरे हाईवा को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे आगे वाला वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

हादसे में एक हाईवा का चालक केबिन में फंस गया। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और चालक को निकालने का प्रयास शुरू किया। रेस्क्यू के लिए क्रेन और ट्रेलर वाहन की मदद ली गई। काफी मशक्कत के बाद चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के कारण एनएच-130 पर करीब एक घंटे तक आवागमन पूरी तरह प्रभावित रहा। सड़क के दोनो ओर यात्री बसों सहित अन्य वाहनो की लंबी कतार लग गई, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

सुशासन तिहार 2026 : मंत्री राजेश अग्रवाल ने लक्ष्मणगढ़ शिविर में हितग्राहियों को वितरित किए विभिन्न योजनाओं के लाभ

- उदयपुर विकासखंड के 4740 आवेदनों का हुआ शत-प्रतिशत निराकरण शिविर में मिले
- विभागीय स्टालों के माध्यम से शासन की योजनाओं की ग्रामीण को मिली जानकारी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,06 मई 2026 (घटती-घटना)।

प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल आज उदयपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ़ में आयोजित 'सुशासन तिहार' के तहत आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने शासन की मंशा के अनुरूप अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने के संकल्प को दोहराया और विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र हितग्राहियों को प्रमाण पत्र व सामग्री का वितरण किया।

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वितरण

शिविर में मंत्री अग्रवाल ने समाज कल्याण विभाग की 'परिवार सहायता योजना' और 'मुख्यमंत्री पेंशन योजना' के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। इसके साथ ही खाद्य विभाग के अंतर्गत राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य विभाग के आयुष्मान कार्ड तथा कृषि विभाग के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड एवं सॉइल हेल्थ कार्ड का वितरण किया गया। योजना का लाभ पाकर ग्रामीणों ने हर्ष व्यक्त किया।

शिकायतों का त्वरित निराकरण

शिविर के दौरान बताया गया कि सुशासन तिहार के अंतर्गत उदयपुर विकासखंड की विभिन्न पंचायतों से पूर्व में प्राप्त 4740 आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में शत-प्रतिशत निराकरण किया जा चुका है। आज के शिविर में मांग 956 एवं शिकायत 65 कुल 1021 नए आवेदन प्राप्त हुए, जिन्हें संबंधित विभागों को समय-बद्ध निराकरण हेतु प्रेषित किया गया है। शिविर स्थल में ही 43 आधार कार्ड, 70 आयुष्मान कार्ड, 32 श्रम कार्ड और 5 नवीन राशनकार्ड बनाएं गए।

गांव-गांव द्वार-द्वार पहुंच रही सुशासन की सरकार

ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में प्रशासन स्वयं जनता के द्वार पहुँच रहा है। जन समस्या निवारण शिविर में ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो रहा है उन्होंने कहा सुशासन तिहार 10 जून तक जारी रहेगा, जहां ग्रामीण मांग और शिकायत आवेदन दे सकते हैं। वहीं उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शेष आवेदनों का अति शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करें। मंत्री अग्रवाल ने युवाओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि वर्तमान में शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस सहित सभी प्रमुख विभागों में भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है, जिससे जल्द ही स्टाफ की कमी दूर होगी और शासकीय सेवाओं में और अधिक सुगमता आएगी।

शराब पीकर बाइक चलाना पड़ा महंगा,कोर्ट ने लगाया 11 हजार जुर्माना

चेकिंग के दौरान भागने की कोशिश,मेडिकल जांच में नशे की पुष्टि,वाहन भी जब्त

-संवाददाता-
बतौली (सरगुजा),06 मई 2026 (घटती-घटना)।

देवरी रोड पर पुलिस की नियमित वाहन चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल चालक को शराब के नशे में वाहन चलाना भारी पड़ गया। मामले में न्यायालय ने आरोपी पर 11,000 का अर्थदंड लगाया है। जानकारी के अनुसार, 29 अप्रैल 2026 को थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा देवरी रोड पर वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान TVS अपाचे मोटरसाइकिल क्रमांक CG15EG 3203 का चालक सोनू कुमार (29 वर्ष), निवासी उरदरा, थाना लुंड्रा, जिला सरगुजा, शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पाया गया। पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास करने पर चालक ने रुकने के बजाय आगे बढ़ने की कोशिश की, जिससे उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगीं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चालक को पकड़ लिया और यातायात नियमों के उल्लंघन पर उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185, 3/181 एवं 29/194(D) के तहत कार्रवाई की गई। इसके बाद चालक का डाक्टरी मुलाहिजा कराया गया, जिसमें उसके शराब सेवन की पुष्टि हुई। पुलिस ने

मोटरसाइकिल जब्त कर आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के बाद 5 मई 2026 को माननीय न्यायालय ने आरोपी चालक पर 11,000 का अर्थदंड लगाया।

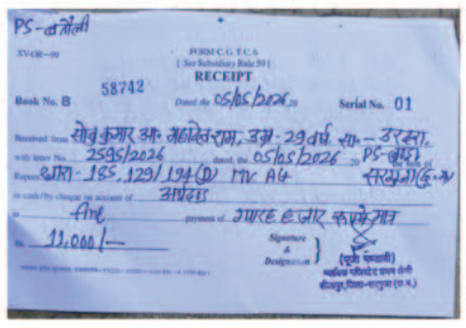

थाना प्रभारी की भूमिका अहम : इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक सेंगर की सक्रिय भूमिका रही। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि शराब पीकर वाहन न चलाएं और यातायात नियमों का पालन करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

भक्तिमय माहौल में कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का भव्य शुभारंभ

-संवाददाता-
सूरजपुर/भैयाथान,06 मई 2026 (घटती-घटना)।

ग्राम डबरीपारा (खुटरा पारा) में सोमवार को श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा महायज्ञ का अत्यंत हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ शुभारंभ हुआ,आयोजन के पहले दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई,जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाएं पीले वस्त्र धारण कर सिर पर मंगल कलश लिए सम्मिलित हुईं। गांव भ्रमण कर भरा गया जल- कलश यात्रा मुख्य यजमानों के गृह निवास से प्रारंभ होकर पूरे गांव का भ्रमण करते हुए कोठाडाड़ तालाब पहुंची, वहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जल भरकर पुनः कथा स्थल तक लाया गया, जहां विधि-विधान से कलश स्थापना की गई। यात्रा के दौरान पूरा क्षेत्र 'राधे-राधे' और 'जय श्री कृष्णा' के जयघोष से गुंजायमान रहा।

कथा व्यास का स्वागत- इस नौ दिवसीय महायज्ञ में कथा वाचक पंडित रविन्द्र महाराज (खड़गवा वाले) अपनी ओजस्वी वाणी से भक्तों को भागवत रसपान करा रहे हैं,कथा के प्रथम दिन महाराज जी ने भागवत महात्म्य पर

प्रकाश डालते हुए कहा कि भागवत कथा के श्रवण से मनुष्य के जन्म-जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है।

मुख्य श्रोता एवं आयोजक-इस आध्यात्मिक अनुष्ठान के मुख्य श्रोता फेकूप्रसाद साहू - कबूतरी साहू एवं शिवनारायण साहू - इंद्रावती साहू हैं, कार्यक्रम को सफल बनाने में साहू परिवार सहित पूरे ग्रामीण क्षेत्र के श्रद्धालु जुटे हुए हैं।

आरा मार्ग पर गिरे पेड़ को हटाया गया,आवागमन पूरी तरह सुचारू रूप से जारी

-संवाददाता-
जशपुरनगर,06 मई 2026 (घटती-घटना)।

आरा की मुख्य सड़क पर तूफान के कारण गिरे पेड़ को हटा दिया गया है। जशपुर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि जैसे ही प्रशासन को पेड़ गिरने की सूचना प्राप्त हुई, तत्काल मौके पर टीम भेजकर पेड़ को हटा दिया गया और मार्ग को सुचारू कर दिया गया। उन्होंने बताया कि सड़क अवरुद्ध होने की स्थिति अधिक समय तक नहीं रही और आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की गई। वर्तमान में उक्त मार्ग पर यातायात पूरी तरह सामान्य रूप से संचालित हो रहा है। उन्होंने कहा कि आपदा अथवा प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न किसी भी बाधा को गंभीरता से लेते हुए त्वरित समाधान किया जाता है। साथ ही आम नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की समस्या की जानकारी तत्काल प्रशासन को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जन सुविधा सर्वोपरि है और ऐसी परिस्थितियों में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करना प्रशासन की प्राथमिकता है।

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा0प्र0क्र0 /20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक गणेश अग्रवाल आ0/पति रामलाल अग्रवाल जाति निवासी भट्ठापारा चौधरी गली अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा मोहल्ला-भट्ठापारा, शीट नम्बर-11 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 4501 /5 रकबा $0.01^{1/2}$ एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से - दिनांक- 11/05/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांकः 22/04/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अम्बिकापुर,सरगुजा

नाम संशोधन संबंधी प्रकरण में सार्वजनिक ईश्तेहार प्रकाशन हेतु

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक जयराम सिंह आ0 अर्जुन सिंह, आयु लगभग 42 वर्ष, जाति खैरवार, निवासी ग्राम फुन्दुरडिहारी, महुआपारा, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़) द्वारा यह आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है -

यह कि आवेदक के पुत्र का नाम पूर्व में रुद्रजय प्रताप सिंह दर्ज है, जिसे अब संशोधित कर रुद्र अजय प्रताप सिंह किया जाना प्रस्तावित है। उक्त नाम संशोधन के संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष आवश्यक आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में विधि अनुसार सार्वजनिक सूचना (ईश्तेहार) का प्रकाशन कराया गया है। आवेदक द्वारा नियमानुसार 5/- (पांच रुपये) का न्याय शुल्क संलग्न कर यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः आज दिनांक से नया नाम रूद्र अजय प्रताप सिंह से सभी शासकीय अशासकीय एवं समस्त दस्तावेज में पढ़ा एवं लिखा जावे जिसके लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

सील — आवेदक जयराम सिंह

कार्यालय प्राचार्य शा0 हाई स्कूल घंघरी,वि0ख0, अम्बिकापुर,सरगगुजा

नाम सुधार संबंधी सार्वजनिक सूचना

यह सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश 'मीतल पैकरा' अंकित हो गया है, जो कि गलत है। जबकि मेरी पुत्री का सही नाम 'चंचल पैकरा' है। मेरी पुत्री का जन्म प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक अभिलेखों में चंचल पैकरा नाम अंकित है जो कि सही एवं वैध नाम है। अतः मीतल पैकरा एवं चंचल पैकरा दोनों नाम एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त माने जाएँ 7 भविष्य में मेरी पुत्री का सही नाम 'चंचल पैकरा' ही मान्य होगा ।

यह सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश 'गुड्डी पैकरा' अंकित हो गया है, जो कि गलत है। जबकि मेरी पुत्री का सही नाम 'श्रुति पैकरा' है। मेरी पुत्री का जन्म प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक अभिलेखों में श्रुति पैकरा नाम अंकित है जो कि सही एवं वैध नाम है। अतः गुड्डी पैकरा एवं श्रुति पैकरा दोनों नाम एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त मने जाएँ । भविष्य में मेरी

पुत्री का सही नाम 'श्रुति पैकरा' ही मान्य होगा ।

नाम - विजय पैकरा
पता - खालपारा बकनाखुर्द ककना, तहसील अंबिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0
दिनांक - 30/04/2026

सील — प्राचार्य शा0हाई0स्कूल घंघरी जिला-सरगुजा,छ0ग0

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2,जिला-सरगुजा,छ0ग0

रा0प्र0क्र0-/अ-6/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक प्रेमचंद यादव आ. हरिकेश्वर यादव, जाति अहीर, निवासी ग्राम चुनापाथर, तहसील रामचंद्रपुर, जिला बलरामपुर छ0ग0 द्वारा ग्राम नेहरूनगर स्थित भूमि खसरा नंबर 101/4 मेसे रकबा 0.020 हे0 भूमि पर से पंजीबद्ध विक्रयपत्र दिनांक 08.01.2024 के आधार पर विक्रेता समय अग्रवाल आ. अजय कुमार अग्रवाल, जाति अग्रवाल, निवासी ब्रम्हरोड सत्तीपारा अम्बिकापुर थाना व तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 मु. नाम आम वास्ते विक्रेता प्रिया राय पत्नी तुषार राय, जाति बाहम्ण, निवासी केदारपुर अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 का नाम विलोपित कराकर उपरोक्त विक्रयपत्र के आधार पर अपना नाम दर्ज कराने बावत् आवेदन पत्र छ0ग0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 110 के तहत् प्रस्तुत किया गया है।

उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 08/05/2026 को न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है । समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 22/04/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी

सील — अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2,जिला-सरगुजा,छ0ग0

रा0प्र0क्र0-/अ-6/2025-26

ईश्तहार

ईश्तहार एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अमन पटेल आ0 अनुपम पटेल, जाति कुनबी, निवासी ग्राम रवेटी, तहसील चन्दौरा सत्तीपारा प्रतापपुर, जिला सूरजपुर छ0ग0 द्वारा ग्राम नेहरूनगर स्थित भूमि खसरा नंबर 101/4 मेसे रकबा 0.020 हे0 भूमि पर से पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 10/03/2025 के आधार पर विक्रेता समय अग्रवाल आ. अजय कुमार अग्रवाल, जाति अग्रवाल, निवासी ब्रम्हरोड सत्तीपारा अम्बिकापुर थाना व तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 मु. नाम आम वास्ते विकेता प्रिया राय पत्नी तुषार राय, जाति बाहम्ण, निवासी केदारपुर अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 का नाम विलोपित कराकर उपरोक्त विक्रयपत्र के आधार पर अपना नाम दर्ज कराने बावत् आवेदन पत्र छ0ग0 भू-राजस्व पर से पंजीबद्ध विक्रयपत्र दिनांक 10.03.2025 संहिता 1959 की धारा 110 के तहत् प्रस्तुत किया गया है।

उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 08/05/2026 को न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है । समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 22/04/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

सील — अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2,जिला-सरगुजा,छ0ग0

रा0प्र0क्र0-/अ-6/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक शुभक कुमार सूर्यवंशी आ. रामशरण सूर्यवंशी, जाति चेरवा, निवासी ग्राम खलिबा, तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 द्वारा ग्राम खलिबा स्थित भूमि खसरा नंबर 60/3, 389/4, 800/9, 1042/1. 1047/4, 1051/35 कुल खसरा नंबर 06 कुल रकबा 0.385 हे. भूमि को दानकर्ता शरण आ0 पुनीस, जाति चेरवा, निवासी ग्राम खलिबा, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 द्वारा दिनांक 10.03.2026 को पंजीबद्ध दान पत्र के माध्यम से कय किया गया है। आवेदक द्वारा पंजीबद्ध दान पत्र के आधार पर विक्रेता का नाम विलोपित कराकर अपना से नामांतरण बावत् आवेदन पेश किया गया है।

उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 22/05/2026 को न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 30/04/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

सील — अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा0प्र0क्र0/..../ 20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रविन्द्र सोनी आ0 / पति रामऔतार सोनी जाति निवासी मायापुर, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा मोहल्ला सदर रोड़, शीट नम्बर-8 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 2577/8,रकबा 0.02,एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 11/05/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांक 22/04/2026को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा0प्र0क्र0/..../20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती रम्भा सोनी आ0/पति रविन्द्र सोनी जाति, निवासी मायापुर, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा मोहल्ला - सदर रोड़, शीट नम्बर-8 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 2573/6,रकबा 0.02 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 11/05/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांकः 22/04/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा0प्र0क्र0/..../20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती रम्भा सोनी आ0/ पति रविन्द्र सोनी जाति, निवासी मायापुर, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा मोहल्ला सदर रोड़, शीट नम्बर-8 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 2577/6,2577/7 रकबा $0.02^{1/4}$,0.03 $^{3/4}$ एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 11./05/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांकः - 22/04/2026को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा0प्र0क्र0/..../20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रविन्द्र सोनी आ0/ पति रामऔतार सोनी जाति,निवासी मायापुर, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा मोहल्ला - सदर रोड़, शीट नम्बर - 8 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 2573/2, 2574/2 रकबा 0.01,0.01 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 11/05/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांकः-22/04/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा0प्र0क्र0/..../20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रजत सोनी, आ0/पति रोहित सोनी आ. रविन्द्र सोनी जाति सोनी निवासी - सदर रोड़ अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा मोहल्ला - सदर रोड़, शीट नम्बर- 8 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 2576/3 रकबा 3120 वर्गफीट भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 11/05/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है । नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांकः- 22/04/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2,जिला-सरगुजा,छ0ग0

रा0प्र0क्र0-/अ-27/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका खुलासो बेवा स्व. नान, निवासी ग्राम बंधवापारा मंदिर के पास असोला, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 द्वारा द्वारा ग्राम असोला स्थित भूमि कुल खसरा न0 14 कुल रकबा 2.250 हे0 भूमि का अनावेदक राम सुरित आ. स्व. पंचम व अन्य, निवासी समलाया मंदिर के पास अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के मध्य खाता विभाजन कराने बावत् आवेदन छ0ग0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा, 178 के तहत् प्रस्तुत की गई है।

उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 22/05/2026 के पूर्व न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 04/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

सील — अतिररिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2

जल संसाधन विभाग की लापरवाही से डूबा सोहत, फूटी नहर ने उजाड़े किसानों के खेत

धान की खेती पर संकट: टूटी नहर, बहता पानी और बर्बादी के मुहाने पर किसान

अब तो जागिए साहब!

टूटी नहर से खेत बने तालाब, सड़क पर बह रहा 'घुनघुट्टा' का पानी

नहर या जंगल? 6 फीट झाड़ियों में गुम हुई सिंचाई व्यवस्था, किसानों पर संकट

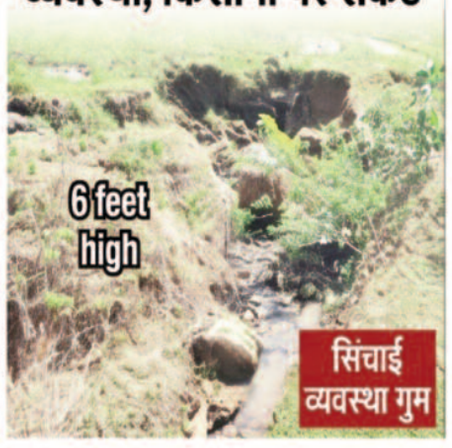

'निराला सिस्टम में बह गया करोड़ों का मेंटेनेंस, खेत डूबे और सड़क बनी नाला'

सुशासन के दावों पर पानी, घुनघुट्टा जलाशय की बदहाली ने खोली विभाग की पोल

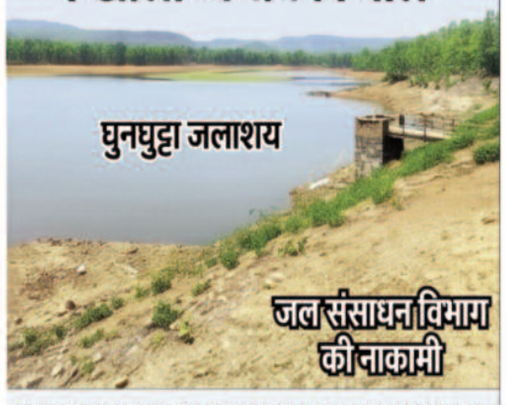

-राजन पाण्डेय-

सोनहत (कोरिया),06 मई 2026 (घटती-घटना)।

कोरिया जिले के जल संसाधन विभाग में मेंटेनेंस अब केवल फाइलों और टेंडरों तक सीमित शब्द बनकर रह गया है,करोड़ों रुपये खर्च होने के दावे हर साल किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि नहरें अब सिंचाई का माध्यम कम और भ्रष्टाचार की बहती हुई निशानी ज्यादा दिखाई देने लगी हैं,जिले में लंबे समय से जमे निराला सिस्टम की चर्चा अब आम हो चुकी है। किसानों का आरोप है कि विभाग में काम कम और ठेकेदारी तंत्र ज्यादा हावी है,परिणाम यह है कि कहीं नहर टूट रही है,कहीं गेट रिस रहा है,तो कहीं पूरी नहर झाड़ियों के नीचे दफन हो चुकी है।

बता दे की सोनहत क्षेत्र का सबसे बड़ा जलाशय 'घुनघुट्टा' कभी इस इलाके की खेती की जीवनरेखा माना जाता था,इसी जलाशय की नहरों से बोडार,कुशहा और आसपास के गांवों तक पानी पहुंचता था और खेतों में हरियाली लहलहाती थी,लेकिन आज वही जलाशय अपनी बदहाली पर आंसू बहाता नजर आ रहा है। हालत यह है कि नहरों में पानी कम और झाड़-झंखाड़ ज्यादा दिखाई देते हैं,किसानों के खेतों तक सिंचाई पहुंचाने वाली नहरें अब खुद पानी में डूबती और टूटती नजर आ रही हैं,घुनघुट्टा जलाशय की यह स्थिति केवल तकनीकी लापरवाही नहीं बल्कि प्रशासनिक उदासीनता और जवाबदेही की कमी का जीवंत उदाहरण है, यदि समय रहते नहरों की सफाई,टूटे हिस्सों की मरम्मत और गेट रिसाव को नहीं रोका गया,तो सोनहत का सबसे बड़ा जलाशय किसानों के लिए वरदान नहीं बल्कि अभिशाप बन जाएगा,आज जरूरत केवल कागजी दावों की नहीं,बल्कि जमीन पर तत्काल कार्रवाई की है। क्योंकि अगर अभी भी जिम्मेदार नहीं जागे,तो आने वाले दिनों में खेतों की हरियाली की जगह केवल बर्बादी का पानी नजर आएगा।

नहर या 6 फीट का जंगल?...जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक उगे झाड़-झंखाड़

घुनघुट्टा जलाशय से निकलने वाली नहरों की हालत देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि यह सिंचाई परियोजना है या फिर किसी परित्यक्त जंगल का हिस्सा,ग्राम अमहर से करीं तक नहरों के भीतर 6-6 फीट ऊंचे पौधे और झाड़ियां उग चुकी हैं,कई स्थानों पर तो नहर पूरी तरह दिखाई तक नहीं देती,दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे विभाग ने नहर निर्माण नहीं बल्कि झाड़ियों की खेती का ठेका दिया हो। नहरों के भीतर जमा कचरा,मिट्टी और विशाल झाड़ियां पानी के प्रवाह को पूरी तरह रोक रही हैं,सवाल यह है कि जब हर साल सफाई और मरम्मत के नाम पर लाखों-करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, तो आखिर यह पैसा जाता कहाँ है?

जल तांडव : फूटी नहर ने खेतों को बनाया तालाब....मुख्य मार्ग हुआ जलमग्न

अमहर से करीं की ओर जाने वाली नहर अब किसानों के लिए राहत नहीं बल्कि तबाही का कारण बन चुकी है, जर्जर और कमजोर हो चुकी नहर बीच रास्ते में फूट गई है,इसके बाद पानी अनियंत्रित होकर किसानों के खेतों में घुस रहा है, जिस खेत में किसान धान की तैयारी कर रहे थे,वहां अब तालाब जैसा दृश्य दिखाई दे रहा है। तेज जलप्रवाह के कारण खेतों की मेड़ें टूट चुकी हैं और कई किसानों की भूमि दलदल में तब्दील हो गई है,स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि खेतों से बहता पानी अब मुख्य पक्की सड़क के ऊपर से गुजर रहा है, सड़क के दूसरी ओर भी अनावश्यक जलभराव हो गया है,जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई महीनों से यह स्थिति बनी हुई है, लेकिन विभाग का कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके तक नहीं पहुंचा।

धान की बुवाई पर संकट...खेत उजाड़ने पर तुला विभाग,कैसे लगेगा 'थरहा'?

धान की खेती शुरू होने में अब महज कुछ सप्ताह शेष हैं, किसान इस समय थरहा (धान नर्सरी) की तैयारी में जुटने वाले थे,लेकिन जल संसाधन विभाग की लापरवाही ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, जहाँ खेत समतल और तैयार होने चाहिए थे,वहाँ अब कीचड़, दलदल और टूटी मेड़ें दिखाई दे रही हैं। किसानों का कहना है कि यदि समय रहते नहर की मरम्मत नहीं हुई और खेतों से अतिरिक्त पानी नहीं निकाला गया,तो इस वर्ष खेती की शुरुआत ही प्रभावित हो जाएगी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस विभाग का गठन किसानों को पानी देने के लिए हुआ, वही विभाग अब किसानों के खेत उजाड़ने का कारण क्यों बन गया है?

करोड़ों का मेंटेनेंस या कागजी खेल?

हर वर्ष नहरों की सफाई,गेट मरम्मत और संरचना सुधार के नाम पर बजट जारी होता है, लेकिन जमीन पर नहरों में उगे जंगल,टूटी संरचनाएं और बहता पानी यह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर यह बजट खर्च कहां हो रहा है? ग्रामीणों का कहना है कि विभाग में काम कम, कागज ज्यादा वाली व्यवस्था चल रही है, ठेके होते हैं,भुगतान होते हैं, लेकिन नहरें जस की तस पड़ी रहती हैं, किसानों के बीच अब यह चर्चा आम हो चुकी है कि विभाग में निराला सिस्टम केवल ठेकेदारों और फाइलों के लिए सक्रिय रहता है, किसानों की समस्याओं के लिए नहीं।

कई महीनों से बह रहा व्यर्थ पानी...प्रशासन की बेरुखी की हद

भीषण गर्मी की दस्तक हो चुकी है, आने वाले दिनों में जल संकट गहराने की आशंका है,इसके बावजूद घुनघुट्टा जलाशय से कई महीनों से लगातार पानी व्यर्थ बह रहा है,यह वही समय है जब हर बूंद पानी बचाने के लिए अभियान चलाए जाते हैं,लेकिन सोनहत में सरकारी तंत्र खुद पानी की बर्बादी का सबसे बड़ा उदाहरण बना हुआ है,ग्रामीणों का कहना है कि यदि यही स्थिति रही, तो जून तक जलाशय का जलस्तर काफी नीचे चला जाएगा और खरीफ सीजन के दौरान किसानों को भारी संकट झेलना पड़ेगा।

एसी कमरों तक सीमित अधिकारी... धरातल पर नहीं होता निरीक्षण...

घुनघुट्टा जलाशय की हालत साफ बताती है कि विभागीय अधिकारी नियमित निरीक्षण नहीं करते, यदि समय-समय पर नहरों का दौरा हुआ होता,तो नहरों में 6 फीट के पौधे नहीं उगते और न ही नहर फूटकर किसानों के खेतों को डुबोती, ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारी केवल दफ्तरों और बैठकों तक सीमित हैं,धरातल पर जाकर वास्तविक स्थिति देखने की जहमत शायद ही कोई उठाता हो,यदि समय रहते निरीक्षण और मरम्मत होती,तो आज किसानों को यह दिन नहीं देखना पड़ता।

क्या 'सुशासन तिहार' में टूटेगी विभाग की नींद?

एक ओर सरकार सुशासन तिहार मनाकर बेहतर प्रशासन और जवाबदेही के दावे कर रही है,वहीं दूसरी ओर घुनघुट्टा जलाशय की तस्वीरें इन दावों को कटघरे में खड़ा कर रही हैं, किसानों का सवाल सीधा है —क्या सुशासन केवल मंचों और भाषणों तक सीमित है? या फिर खेतों तक पानी पहुंचाने और किसानों की बर्बादी रोकने में भी दिखाई देगा? अब देखना यह है कि विभाग की कुंभकर्णी नींद टूटती है या फिर किसान यूं ही अपनी बर्बादी देखते रहेंगे।

विभाग की 'निराली' कार्यशैली...गेट से रिसाव जारी...टेल एरिया तक नहीं पहुंच रहा पानी

घुनघुट्टा जलाशय में एक ओर पानी लगातार रिसकर व्यर्थ बह रहा है,वहीं दूसरी ओर टेल एरिया के किसान पानी के लिए तरस रहे हैं,मुख्य गेट से महीनों से पानी का रिसाव जारी है,ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग को इसकी जानकारी होने के बावजूद कोई तकनीकी सुधार नहीं किया गया,विडंबना यह है कि जहां जरूरत नहीं है वहां पानी बहकर खेत और सड़क डुबो रहा है,जबकि जिन किसानों के खेतों तक सिंचाई पहुंचनी चाहिए,वहां नहरों में पानी ही नहीं पहुंच पा रहा, यह स्थिति विभाग के रखरखाव और निगरानी के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है।

मजबूत विवेचना बनी इंसाफ की नींव, सूरजपुर पुलिस की सशक्त कार्रवाई से हत्या मामले में दो आरोपियों को 10-10 साल की सजा

परी में युवक को पेड़ से बांधकर मारपीट करने का मामला,न्यायालय ने सुनाई कठोर सजा और जुर्माना

-संवाददाता-
सूरजपुर,06 मई 2026 (घटती-घटना)।

कहा जाता है कि न्यायालय में न्याय की शुरुआत थाने की विवेचना से होती है,यदि पुलिस सही दिशा में निष्पक्ष और मजबूत जांच करे,साक्ष्यों को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करे और केस डायरी को तथ्यात्मक रूप से तैयार करे,तो अपराधियों को सजा तक पहुंचाना आसान हो जाता है, सूरजपुर जिले में ऐसा ही एक उदाहरण सामने आया है,जहां पुलिस की मजबूत विवेचना और सटीक दस्तावेजीकरण के आधार पर न्यायालय ने हत्या के मामले में दो आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

मामला वर्ष 2024 के मई माह का है, जब थाना सूरजपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम परी में एक युवक को पेड़ से बांधकर बेरहमी से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया था, गंभीर रूप से घायल युवक की मौत के बाद पुलिस ने मामले को हत्या से संबंधित धाराओं में दर्ज कर विवेचना शुरू की थी, प्रकरण की सुनवाई एडीजे (अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश) सूरजपुर श्री डी.के. गिलहरे की अदालत में हुई। न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान और पुलिस

विवेचना को महत्वपूर्ण मानते हुए दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304/34 के तहत दोषी करार दिया, न्यायालय ने आरोपी रामसाय सिंह एवं शिवचरण सिंह को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही आदेश में कहा गया है कि जुर्माना राशि जमा नहीं करने की स्थिति में दोनों आरोपियों को अतिरिक्त एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा, सूरजपुर न्यायालय का यह फैसला केवल दो आरोपियों को सजा देने भर का मामला नहीं है,बल्कि यह इस बात का उदाहरण भी है कि यदि पुलिस विवेचना मजबूत हो, साक्ष्य व्यवस्थित हों और अभियोजन प्रभावी हो, तो न्याय की राह आसान हो जाती है, यह निर्णय कानून व्यवस्था में जनता के विश्वास को मजबूत करने वाला माना जा रहा है।

पेड़ से बांधकर की गई थी मारपीट,मई 2024 में दर्ज हुआ था मामला- अदालती दस्तावेजों के अनुसार यह मामला थाना सूरजपुर के अपराध क्रमांक 290/2024 से संबंधित है, घटना 26 मई 2024 की बताई गई है, जबकि एफआईआर 27 मई 2024 को दर्ज की गई थी, सूरजपुर कोतवाली पुलिस थाना प्रभारी विमलेश दुबे ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए साक्ष्य संकलित किए,गवाहों के बयान दर्ज किए और न्यायालय में मजबूत तरीके से अभियोजन प्रस्तुत किया, इसी का परिणाम रहा कि लगभग दो वर्ष के भीतर मामले में फैसला सुनाया गया।

मजबूत विवेचना से मजबूत न्याय, पुलिस की भूमिका रही अहम- कानूनी जानकारों का मानना है कि किसी भी आपराधिक मामले में पुलिस विवेचना सबसे अहम कड़ी होती है, यदि शुरुआती स्तर पर लापरवाही हो जाए, तो कई बार गंभीर मामलों में भी आरोपी बच निकलते हैं,इस मामले में पुलिस द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य संकलन, गवाहों के बयान और अभियोजन पक्ष के साथ समन्वय मजबूत रहा, जिसके कारण न्यायालय के समक्ष मामला प्रभावी ढंग से प्रस्तुत हो सका।

न्यायालय का स्पष्ट संदेश,कानून हाथ में लेने वालों को नहीं मिलेगी राहत- न्यायालय के इस फैसले को कानून व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है,फैसले ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती,पेड़ से बांधकर मारपीट जैसी अमानवीय घटना पर न्यायालय की कठोर टिप्पणी और सजा यह दर्शाती है कि ऐसे मामलों में न्यायपालिका संवेदनशील और सख्त रुख अपना रही है।

पीड़ित पक्ष को मिला न्याय- फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने राहत महसूस की है। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर इस प्रकार की घटनाओं में साक्ष्य और गवाहों के अभाव में मामले कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन इस प्रकरण में पुलिस और अभियोजन की सक्रियता ने पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

शोक समाचार

श्रीमती केशर देवी गोयल का निधन,नगर में शोक की लहर

-संवाददाता-
सूरजपुर,06 मई 2026 (घटती-घटना)।

नगर के भैयाथान रोड निवासी स्वर्गीय दिलीपचंद गोयल की धर्मपत्नी श्रीमती केशर देवी गोयल का 85 वर्ष की आयु में दुःखद निधन हो गया, उनके निधन की खबर से परिवार, रिश्तेदारों एवं नगरवासियों में शोक व्याप्त है, स्वर्गीय श्रीमती केशर देवी गोयल सरल, धार्मिक एवं मिलनसार स्वभाव की महिला थीं, वे समाज में अपने सौम्य व्यवहार और पारिवारिक मूल्यों के लिए जानी जाती थीं। वे महावीर गोयल, मदन गोयल एवं मुकेश गोयल की माताश्री थीं, उनका अंतिम संस्कार स्थानीय नमदगिरी रेणुका नदी तट स्थित मुक्तिधाम में किया गया, जहां बड़ी संख्या में परिजन, शुभचिंतक एवं नगरवासी उपस्थित होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोक संतप्त परिवार को इस दुख की घड़ी में संबल दें।

सही दवा-शुद्ध आहार या सब सेट है सरकार?

अभियान की गाड़ियों के सायरन गूंजे, मगर नकली पनीर अब भी बाजार का राजा

जांच के नाम पर खानापूर्ति, शादी सीजन में 'केमिकल भोज' परोसने वालों पर मेहरबान सिस्टम!

मिलावट का मौसम,अभियान का अभिनय

गर्मी का मौसम आते ही दूध फटने लगता है,ब्रेड खराब होने लगती है और मिठाइयों की गुणवत्ता गिरने लगती है,लेकिन जिले में मिलावट का कारोबार इतना आधुनिक हो चुका है कि अब असली और नकली का फर्क पहचानना मुश्किल हो गया है,बाजार में ऐसा पनीर बिक रहा है जो शायद दूध से कम और केमिकल से ज्यादा बना है,खोया ऐसा कि गाय-भैंस भी देख लें तो पहचानने से इंकार कर दें,लेकिन यह सब खुलेआम बिक रहा है और जिम्मेदार विभाग अभियान चलाने में व्यस्त हैं, लोग अब मजाक में कहने लगे हैं — जितना शुद्ध अभियान का नाम है, उतनी ही अशुद्ध बाजार की हालत है।

जांच से पहले पहुंच जाता है संदेश! साहब आ रहे हैं, फ्रिज बदल दो

सूत्रों की मानें तो जिले में चल रहा यह सघन जांच अभियान इतना गोपनीय है कि जांच से पहले ही संबंधित दुकानदारों तक सूचना पहुंच जाती है, यानी अचानक छापा कम और पूर्व सूचना वाला दौरा ज्यादा हो रहा है,बताया जा रहा है कि जैसे ही टीम निकलती है,वैसे ही कुछ दुकानों में सफाई अभियान शुरू हो जाता है। खराब सामान पीछे के कमरे में पहुंच जाता है,नकली पनीर गायब हो जाता है और कर्मचारियों को आज दस्ताने पहन लो वाला आदेश जारी हो जाता है,कुछ दुकानदार तो मजाक में यह भी कहते सुने गए —सरकारी जांच का टाइमटेबल अब हमसे ज्यादा किसे पता होगा?

नकली पनीरः शादी सीजन का असली हीरो

जिले में शादी-विवाह का सीजन शुरू होते ही पनीर की मांग तेजी से बढ़ जाती है, लेकिन असली दूध से बने पनीर की लागत और बाजार में बिकने वाली कीमत का हिसाब जोड़ें तो कहानी खुद समझ में आ जाती है, सूत्र बताते हैं कि जिस कीमत पर कई डेयरी और दुकानदार पनीर बेच रहे हैं,उस दर पर असली पनीर बनाना संभव ही नहीं है। यानी या तो विज्ञान बदल गया है या फिर पनीर की परिभाषा, अब यह नकली पनीर होटल से लेकर शादी समारोह तक हर जगह पहुंच चुका है। लोग समझ रहे हैं कि वे शाही पनीर खा रहे हैं, जबकि असल में शरीर में केमिकल और सिंथेटिक पदार्थ पहुंच रहे हैं, स्वास्थ्य विशेषज्ञों की मानें तो ऐसा नकली पनीर पेट, लीवर, किडनी और पाचन तंत्र के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है,लेकिन यहां सवाल स्वास्थ्य का नहीं, मुनाफे का है।

-रवि सिंह-

बैकुंठपुर/कोरिया,06 मई 2026 (घटती-घटना)।

जिले में इन दिनों सही दवा, शुद्ध आहार अभियान बड़े जोर-शोर से चल रहा है, पोस्टर लग रहे हैं,टीम निकल रही है,फोटो खिंच रहे हैं,प्रेस नोट जारी हो रहे हैं और जनता को भरोसा दिलाया जा रहा है कि अब मिलावटखोरों की खैर नहीं,लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि मिलावटखोरों के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि मुस्कान दिखाई दे रही है,वजह भी साफ है उन्हें पता है कि यह अभियान ज्यादा दिन का मेहमान नहीं, केवल मौसम की तरह आया है और चला जाएगा,जिले में नकली पनीर, केमिकल वाला खोया,बासी ब्रेड,गंदे तेल में तले खाद्य पदार्थ और अमानक मिठाइयों का कारोबार धड़ल्ले से जारी है,शादी-विवाह का सीजन शुरू होते ही मिलावटखोरों की फैक्ट्रियां भी फुल स्पीड में चलने लगी हैं,लेकिन जिम्मेदार विभागों की कार्यशैली देखकर ऐसा लगता है मानो अभियान जनता के लिए नहीं, बल्कि फाइलों और फोटो एल्बम के लिए चलाया जा रहा हो।

जनता पूछ रही है

- जांच से पहले सूचना कौन पहुंचा रहा है?
- नकली पनीर बेचने वालों पर बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
- शादी सीजन में खाद्य पदार्थों की विशेष जांच क्यों नहीं?
- चौपाटियों और ठेलों की सफाई जांच का हिस्सा क्यों नहीं?
- क्या सही दवा-शुद्ध आहार केवल 15 दिन का सरकारी उत्सव है?

नियत बदले बिना नहीं बदलेगी व्यवस्था

सच यह है कि अभियान से ज्यादा जरूरत सिस्टम की नीयत बदलने की है, क्योंकि मिलावटखोरी केवल खाद्य पदार्थों में नहीं,अब व्यवस्था में भी दिखाई देने लगी है, जब तक कार्रवाई का डर नहीं होगा,नकली पनीर असली बनकर बिकता रहेगा,बासी ब्रेड ताजी बताकर परोसी जाती रहेगी और जनता सही दवा-शुद्ध आहार के नाम पर केवल भाषण सुनती रहेगी,अब देखना यह है कि जिम्मेदार विभाग इस अभियान को सचमुच जनता की सुरक्षा का माध्यम बनाते हैं या फिर यह भी बाकी अभियानों की तरह फाइलों में बंद होकर रह जाएगा।

सेटिंग,कमिशन और सिस्टम की चुप्पी

जिले में यह चर्चा अब खुलकर होने लगी है कि खाद्य कारोबारियों और जिम्मेदारों के बीच सेटिंग का खेल चलता है,सूत्रों की मानें तो कुछ दुकानदारों को पहले से ही भरोसा रहता है कि उन तक कार्रवाई पहुंचेगी ही नहीं, यही वजह है कि नकली खाद्य पदार्थ बेचने वाले बेखौफ हैं और आम जनता असुरक्षित, यदि वास्तव में सख्ती होती,तो अब तक कई डेयरियों, होटल और चौपाटियों पर ताले लग चुके होते,लेकिन फिलहाल तो स्थिति ऐसी है कि मिलावटखोरों का कारोबार और विभाग का अभियान दोनों साथ-साथ आराम से चल रहे हैं।

चौपाटी और ठेलों में 'स्वच्छता' छुट्टी पर

जिला मुख्यालय की कई चौपाटियों,गुमटियों और ठेलों की हालत देखकर ऐसा लगता है कि स्वच्छता अभियान ने इन क्षेत्रों में प्रवेश करने से पहले ही हार मान ली, खुले में रखे खाद्य पदार्थ, धूल-मिट्टी से भरे बर्तन,काले पड़ चुके तेल में तलते पकवान और दूषित पानी का इस्तेमाल आम बात बन चुकी है,गर्मी के दिनों में जल्दी खराब होने वाली ब्रेड और खाद्य सामग्री भी धड़ल्ले से उपयोग की जा रही है, लेकिन जांच टीमों की नजर शायद वहां तक नहीं पहुंचती,जहां असली खतरा मौजूद है, क्योंकि असली खतरे पर कार्रवाई करने के लिए केवल अभियान नहीं, हिम्मत और नियत भी चाहिए।

फोटो में सख्ती,जमीन पर नरमी

अभियान के दौरान सबसे तेज चीज अगर चल रही है, तो वह है कैमरा। जांच के दौरान सैंपल लेते हुए तस्वीरें, अधिकारियों की मीटिंग,दुकानदारों को समझाइश — सबकुछ व्यवस्थित तरीके से हो रहा है, बस जो नहीं हो रहा, वह है बड़ी कार्रवाई,अब तक न तो किसी बड़े नकली पनीर कारोबारी पर सख्त कार्रवाई सामने आई, न ही किसी होटल या डेयरी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ,ऐसे में जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर यह अभियान कार्रवाई के लिए चल रहा है या प्रचार के लिए?

सैंपलिंग जारी है — सिस्टम का सबसे सुरक्षित जवाब

जब भी सवाल उठता है कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई,तो एक जवाब तुरंत तैयार मिलता है सैंपलिंग की गई है, रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी,यह वही रिपोर्ट है जो कई बार इतनी देर से आती है कि तब तक मौसम बदल जाता है,दुकान का बोर्ड बदल जाता है और अभियान भी खत्म हो जाता है,जनता अब यह समझ चुकी है कि रिपोर्ट आने वाली है सरकारी शब्दकोश का सबसे सुरक्षित वाक्य है।

सुशासन के पोस्टर चमक रहे, किसान प्यास से तड़प रहे!

चांदनी बिहारपुर के धान खरीदी केंद्रों में पानी नहीं,भीषण गर्मी में रोज परेशान हो रहे सैकड़ों किसान

नवगई और मोहरसोप समिति में पेयजल संकट,धान खरीदी बंद फिर भी रोज पहुंच रहे किसान...बोरिंग और सोलर पंप की मांग तेज

-ओंकार पाण्डेय-

चांदनी बिहारपुर/सूरजपुर,06 मई 2026 (घटती-घटना)।

एक तरफ सरकार सुशासन त्योहार मना रही है,योजनाओं और सुविधाओं के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं,वहीं दूसरी तरफ सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर क्षेत्र की हकीकत इन दावों को पसीने में बहाती नजर आ रही है। यहां किसान धान बेचने नहीं, अब पानी खोजने समिति पहुंच रहे हैं।

आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्यादित नवगई और मोहरसोप धान खरीदी केंद्रों में पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा तक उपलब्ध नहीं है,हालात ऐसे हैं कि भीषण गर्मी में रोज सैकड़ों किसान समिति पहुंचते हैं,लेकिन उन्हें पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं हो रही, धान खरीदी भले बंद हो चुकी हो,लेकिन समितियों में किसानों का आना-जाना लगातार जारी है,खाद-बीज,दस्तावेज, खाते और अन्य कार्यों के लिए किसान रोज यहां पहुंचते हैं। मगर विडंबना देखिए कि किसानों के नाम पर चलने वाली समितियों में किसानों के लिए पानी तक नहीं है।

सुशासन के बैनर तले प्यासा किसान, कागजों में सुविधा,जमीन पर सूखा

चांदनी बिहारपुर की इन समितियों में स्थिति ऐसी है कि किसान घंटों तक गर्मी में बैठकर अपने काम का इंतजार करते हैं,लेकिन प्यास बुझाने के लिए उन्हें इधर-उधर भटकना पड़ता है,कुछ किसान घर से बोतल लेकर आते हैं, तो कई पास के गांवों या दुकानों की ओर पानी खोजने निकल जाते हैं। जो किसान दूरदराज इलाकों से आते हैं,उनकी परेशानी और बढ़ जाती है, गर्मी का तापमान लगातार बढ़ रहा है,लेकिन जिम्मेदारों की संवेदनाएं शायद एसी कमरों से बाहर नहीं निकल पा रहीं,अब क्षेत्र में लोग तंज कसते हुए कह रहे हैं समिति में धान तौलने का कांटा है,लेकिन पानी नापने के लिए एक बूंद भी नहीं।

धान खरीदी बंद,लेकिन परेशानी चालू

अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि धान खरीदी खत्म होने के बाद समितियों में भीड़ कम हो जाती है,लेकिन नवगई और मोहरसोप समितियों की हकीकत इससे अलग है, यहां किसान सालभर किसी न किसी कार्य से पहुंचते हैं,बैंकिंग संबंधी काम,दस्तावेज सुधार, खाद-बीज जानकारी और अन्य प्रक्रियाओं के कारण रोज सैकड़ों लोगों का आना-जाना बना रहता है,इसके बावजूद पानी जैसी न्यूनतम सुविधा उपलब्ध नहीं होना सीधे तौर पर प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है।

समिति या तपता हुआ प्रतीक्षालय?

नवगई और मोहरसोप समितियों की स्थिति देखकर ऐसा लगता है मानो किसान सुविधा केंद्र नहीं, बल्कि गर्मी की परीक्षा देने पहुंचे हों,ना पानी,ना छांव की पर्याप्त व्यवस्था और ना ही कोई वैकल्पिक इंतजाम,कई बुजुर्ग किसान घंटों प्यासे बैठे रहते हैं, कुछ लोग मजबूरी में गर्म पानी पीने को विवश हैं,सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब प्रशासन करोड़ों की योजनाओं का दावा करता है, तो क्या एक बोरिंग और सोलर पंप लगाना इतना मुश्किल काम है?

सुशासन त्योहार और जमीनी हकीकत

इन दिनों प्रदेश में सुशासन त्योहार का प्रचार जोर-शोर से किया जा रहा है,गांव-गांव तक प्रशासनिक संवेदनशीलता और बेहतर व्यवस्था के संदेश पहुंचाए जा रहे हैं,लेकिन चांदनी बिहारपुर की तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं, यहां किसान पूछ रहे हैं – जब पानी जैसी मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही,तो फिर सुशासन आखिर किसे कहते हैं? कई ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की योजनाएं कागजों और भाषणों में ज्यादा दिखाई देती हैं,जमीन पर कम।

किसानों की मांगः तत्काल लगे बोरिंग और सोलर पंप

क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, सूरजपुर कलेक्टर और छत्तीसगढ़ शासन से मांग की है कि नवगई और मोहरसोप समितियों में जल्द से जल्द बोरिंग कराकर सोलर पंप स्थापित किया जाए, किसानों का कहना है कि यह केवल सुविधा का नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और सम्मान का भी मामला है, भीषण गर्मी में पानी के बिना लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

बढ़ सकता है आक्रोश

यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ,तो किसानों का आक्रोश बढ़ सकता है। क्षेत्र में अब यह चर्चा तेज हो रही है कि यदि समितियों में पानी जैसी बुनियादी सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती,तो फिर किसानों के हितों के दावे किस काम के? अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस गंभीर समस्या को केवल शिकायत मानता है या फिर इसे प्राथमिकता देकर स्थायी समाधान की दिशा में कदम उठाता है।

प्यास से हालत खराब हो जाती है किसानों ने बयां किया दर्द...

किसानों का कहना है कि भीषण गर्मी में बिना पानी के घंटों तक समिति में बैठना बेहद कठिन हो गया है...

हम लोग रोज यहां आते हैं,धान के अलावा भी बहुत काम रहता है,लेकिन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, गर्मी में हालत खराब हो जाती है।

राजेश नामक किसान

धान खरीदी बंद होने के बाद भी हम लोग समिति आते हैं,लेकिन पानी नहीं मिलता। बहुत परेशानी हो रही है।

रामकुमार नामक किसान

रामचंद्र ने सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा...सरकार सुशासन की बात करती है, लेकिन यहां बुनियादी सुविधा तक नहीं है। बोरिंग और सोलर पंप लगना जरूरी है।

—रामचंद्र नामक किसान

वहीं रामचरन नामक किसान का कहना है —सैकड़ों किसान रोज आते हैं, फिर भी पानी नहीं है। हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए।

— रामचरन नामक किसान

सलमान खान की फिल्म के लिए टेंशन बनी प्रभास की अपकमिंग थ्रिलर,ईद पर होगा महा क्लैश

साउथ सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म का क्लैश आने वाले समय में सलमान खान की इस बड़ी फिल्म से होगा। मौजूदा समय में सुपरस्टार सलमान खान का नाम उनकी आने वाली फिल्मों को लेकर चर्चा में बना हुआ है। जिसमें साउथ सिनेमा के मशहूर निर्देशक वामशी पेडिपल्ली और निर्माता दिल राजू की एक अनटाइटल मूवी भी शामिल है, जिसे अगले साल 2027 में ईद पर रिलीज किया जाएगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सलमान की इस मूवी राह आसान नहीं होने वाली है और साउथ सुपरस्टार प्रभास उन्हें कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार हैं। उनकी एक मोस्ट अवेटेड फिल्म की रिलीज डेट भी ईद 2027 फाइनल की गई है, वह कौन सी फिल्म है।

ईद पर रिलीज होगी प्रभास की ये फिल्म

फेस्टिव सीजन के लिए फिल्मेकर्स और स्टार्स पहले से तैयारी कर लेते हैं। ईद के मौके पर भी सिनेमाघरों में बड़े-बड़े फिल्म कलाकारों की मूवीज देखने को मिलती हैं। इस मामले में सलमान खान का नाम टॉप पर रहता है, जिनकी ज्यादातर मूवीज ईद पर आती हैं। वामशी पेडिपल्ली के फिल्म के लिए भी सलमान ने ईद की रिलीज डेट लॉक की है, लेकिन उनकी इस मूवी को प्रभास की स्पिरिट से कड़ी टक्कर मिलेगी। जी हां कबीर सिंह और एनिमल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाने वाले संदीप रेड्डी वांगा स्पिरिट को पोस्टपॉन नहीं करना चाहते हैं और उन्होंने अपनी इस अपकमिंग फिल्म की रिलीज डेट बदलने से इनकार कर दिया है। फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर ट्वीट कर इस मामले की आधिकारिक जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि 5 मार्च 2027 को स्पिरिट को थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। बता दें कि अगले साल 10 मार्च को ईद का जश्न मनाया जाएगा। ऐसे में आपको बॉक्स ऑफिस पर सलमान खान की अनटाइटल फिल्म और प्रभास की स्पिरिट के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलेगी।

प्रभास की अन्य मूवीज

सिर्फ संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट ही नहीं बल्कि आने वाले समय में प्रभास कई मूवीज में नजर आएंगे,जिनमें सालार पार्ट 2 और फौजी के नाम शामिल हैं। इसके अलावा निर्देशक नाग अश्विन की कल्कि 2 भी पाइपलाइन में मौजूद है।

189 दिनों तक थिएटर्स में लगातार चली थी विनोद खन्ना की फिल्म

दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना ने अपने फिल्मी करियर में एक ऐसी मूवी दी थी,जो 27 हफ्तों तक सिनेमाघर में चली थी। विनोद खन्ना हिंदी सिनेमा के वह अभिनेता थे,जिनकी पर्सनैलिटी की चर्चा आज भी जाती है। जब वह पर्दे पर एंट्री मारते थे, तब सिनेमाघरों में सीटियां सुनाई देती थीं। इंडस्ट्री में उनका कद इतना बड़ा था, जिसकी छाप आज भी कायम है।
इस बीच हम आपको विनोद खन्ना के करियर की उस फिल्म बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसने हिंदी सिनेमा की परिभाषा को बदलकर रख दिया था। एक्टर की वह फिल्म 27 हफ्तों तक यानी करीब 189 दिनों तक सिनेमाघर में सफलतापूर्वक चली थी। विनोद खन्ना की कौन सी ब्लॉकबस्टर फिल्म के बारे में चर्चा की जा रही है।

विनोद खन्ना की ब्लॉकबस्टर फिल्म

अभिनेता विनोद खन्ना हिंदी सिनेमा के उन चुनिंदा कलाकारों में शुमार थे,जो पर्दे पर लीड हीरो के रोल के अलावा एंटी हीरो बनकर भी अपनी छाप छोड़ने में सफल होती थे। ऐसा ही कमाल उन्होंने 55 साल पहले सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म मेरा गांव मेरा देश में करके दिखाया था। इस फिल्म में विनोद खन्ना के अलावा धर्मेंद्र और आशा पारेख जैसे अन्य कई कलाकार मौजूद रहे थे। मेरा गांव मेरा देश में विनोद ने खूंखार डकैत जब्बर सिंह की भूमिका को अदा किया था। जिस तरह से विनोद ने ये नेगेटिव किरदार अदा किया था, उससे वह फिल्म में धर्मेंद्र के रोल पर भी भारी पड़े थे। फिल्म की कहानी और गाने काफी शानदार रहे, जिसकी वजह से मेरा गांव मेरा देश बॉक्स ऑफिस पर भी सफल रही थी। यही कारण था जो मेरा गांव मेरा देश सिल्वर जुबली भी रही थी और 27 हफ्तों तक सिनेमाघरों में चलती रही थी। 189 दिनों से ज्यादा समय तक मुंबई के एक थिएटर में विनोद खन्ना की इस मूवी के चार शोज लगातार चलते रहे थे।

साल की सबसे बड़ी हिट रही थी मेरा गांव मेरा देश

गौर किया जाए मेरा गांव मेरा देश की कमर्शियल परफॉर्मेंस की तरफ तो साल 1971 में रिलीज होने वाली हिंदी फिल्मों में कमाई में ये मूवी टॉप पर रही थी। माना जाता है कि मेरा गांव मेरा देश के बाद ही निर्देशक रमेश सिप्पी को शोले जैसी कल्ट मूवी बनाने का फैसला लिया था।

जान्हवी शाहिद की नई कॉमेडी फिल्म चर्चा में

जान्हवी कपूर और शाहिद कपूर के एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ आने की खबरें फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों कलाकार एक नई रिलेशनशिप कॉमेडी फिल्म में साथ नजर आ सकते हैं। यह प्रोजेक्ट अभी शुरुआती बातचीत के चरण में है और अगर सब कुछ फाइनल होता है तो यह दोनों का पहला पूरा ऑन-स्क्रीन कोलेबोरेशन होगा। जान्हवी कपूर ने इससे पहले 2024 की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में एक कैमियो किया था, जिसमें शाहिद कपूर और कृति सेनन मुख्य भूमिकाओं में थे। उस फिल्म में जान्हवी की छोटी सी मौजूदगी और शाहिद के साथ उनकी स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने काफी पसंद किया था।

इसी के बाद से दोनों के एक साथ किसी बड़े प्रोजेक्ट में आने की अटकलें तेज हो गई थीं। इसी बीच अब नई रिपोर्ट सामने आई है कि दोनों कलाकारों के बीच एक नई फिल्म को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार, यह फिल्म पूरी तरह से एक रिलेशनशिप कॉमेडी होगी, जिसमें कहानी आधुनिक रिश्तों, भावनाओं और हल्के-फुल्के हास्य के इर्द-गिर्द घूमेगी। बताया जा रहा है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट को रिलेटेबल और एंटरटेनिंग रखने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि युवा दर्शकों से जुड़ाव बनाया जा सके। फिल्म से जुड़े सूत्रों के अनुसार, जान्हवी कपूर इस प्रोजेक्ट के लिए फीमेल लीड के तौर पर एडवांस्ड बातचीत कर रही हैं। अगर यह डील फाइनल हो जाती है, तो यह उनके करियर का एक नया सहयोग होगा। वहीं शाहिद कपूर भी लंबे समय बाद कॉमेडी जॉनर में वापसी करने को लेकर उत्साहित बताए जा रहे हैं। इंडस्ट्री से जुड़े जानकारों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर शुरुआती स्तर पर सकारात्मक माहौल है, लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। अगर यह फिल्म बनती है, तो दर्शकों को एक नई और हल्की-फुल्की रिलेशनशिप स्टोरी देखने को मिल सकती है, जिसमें जान्हवी और शाहिद की जोड़ी पहली बार बड़े रोल में साथ नजर आएगी। फिलहाल, इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी दोनों कलाकारों की जोड़ी को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

दीपिका पादुकोण की किंग शूट से फैंस ने देखा एक्टर का ताज़ा लीक वीडियो

सिद्धार्थ आनंद की डायरेक्ट की हुई किंग मूवी के सेट से लगातार लीक हो रही हैं, जिसकी शूटिंग अभी केप टाउन में हो रही है। इससे पहले दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान के एक गाने की शूटिंग के वीडियो ऑनलाइन वायरल हुए थे। ताज़ा लीक में, दोनों एक्टर बीच साइड पर एक सीन की शूटिंग करते हुए देखे जा सकते हैं। हालांकि, जिस चीज़ ने सोशल मीडिया यूज़र्स का ध्यान खींचा, वह थी दीपिका पादुकोण का साथ।
किंग की शूटिंग में दीपिका पादुकोण के साथ रणवीर सिंह और दुआ?
दीपिका पादुकोण, जो अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रही हैं, खबर है कि अगस्त में काम पर रहते हुए भी उनके साथ हैं। मूवी के सेट से लीक हुए एक वीडियो में फैंस की नज़रें रणवीर सिंह और उनकी बेटी दुआ पर टिकी हैं, जो एक्ट्रेस के साथ हैं।
सोशल मीडिया यूज़र्स के मुताबिक, धुरंधर एक्टर को बच्चे को गोद में लिए साइडलाइन में खड़े देखा गया, जबकि दीपिका मूवी के लिए एक रोमांटिक मोंटाज शूट कर रही थीं। हालांकि वीडियो और दावों की असलियत को अलग से वेरिफाई किया जा सकता है, लेकिन सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह की तारीफ़ों का तांता लगा हुआ है। कुछ नेटिज़न्स यह भी शेयर कर रहे हैं कि किंग की शूटिंग कपल के लिए बेबीमून का भी काम कर रही है। जहाँ रणवीर सिंह धुरंधर की सक्सेस का मज़ा ले रहे हैं, वहीं दीपिका अपने मैटरनिटी ब्रेक से पहले अपने वर्क कमिटमेंट्स पूरे कर रही हैं। मूवी शूट से पहले लीक हुई तस्वीरों में, दीपिका का बेबी बंप भी फैंस ने देखा था। रामलीला स्टार्स ने 19 अप्रैल को एक इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की खबर कन्फर्म की। हालाँकि,यह पता नहीं है कि दीपिका प्रेग्नेंसी के किस स्टेज में हैं।

आलोचना पर सोचकर जवाब देना सीखा

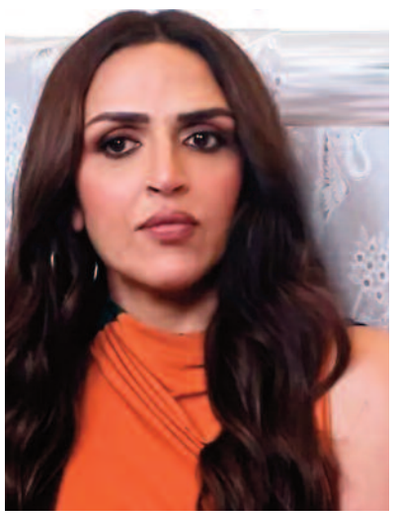

अभिनेत्री ईशा देओल ने अपने लंबे करियर और मीडिया के बदलते दौर को लेकर एक खुलकर बातचीत में कई अहम बातें साझा की हैं। उन्होंने बताया कि समय के साथ उन्होंने आलोचना से निपटने और सार्वजनिक प्रतिक्रिया देने के तरीके में बड़ा बदलाव किया है। ईशा देओल ने स्वीकार किया कि उम्र और अनुभव ने उन्हें रिएक्ट करने से पहले सोचने की अहमियत सिखाई है। ईशा देओल ने कहा कि उन्होंने अपने करियर के दौरान मीडिया के कई दौर देखे हैं–मैगज़ीन संस्कृति से लेकर आज के सोशल मीडिया युग तक। उनके अनुसार, पहले का दौर अलग था जब कलाकारों को लेकर मैगज़ीन में कई तरह की बातें छपती थीं, लेकिन उन्होंने कभी भी उस तरह की आलोचना पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी।

खेल समाचार

नहीं होगा भारत-पाक महामुकाबला?

खेल मंत्रालय के नए आदेश ने तोड़ा करोड़ों का दिल

नई दिल्ली,06 मई 2026। भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी खेल के मैदान पर भिड़ंत होती है, तो रोमांच अपनी चरम सीमा पर होता है। विशेषकर क्रिकेट के मैदान पर इन दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वियों का आमना-सामना पूरी दुनिया का ध्यान खींचता है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों से राजनीतिक तनाव और सुरक्षा कारणों से दोनों देशों के बीच खेल संबंधों को लेकर भारी अनिश्चितता बनी हुई थी। विशेष रूप से एशिया कप और वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंटों के आयोजन स्थल और भागीदारी को लेकर विवाद गहराता रहा है। इसी अनिश्चितता को समाप्त करते हुए अब भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर अपनी नीति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। इस फैसले का सीधा असर दोनों देशों के खेल भविष्य और आगामी टूर्नामेंटों पर पड़ेगा।
6 मई को खेल मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा सर्कुलर ने यह साफ कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय खेल आयोजनों पर लगा प्रतिबंध फिलहाल जारी रहेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारतीय टीमें किसी भी स्वतंत्र श्रृंखला के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगी और न ही पाकिस्तानी टीमों को भारत में द्विपक्षीय मुकाबलों के लिए आमंत्रित किया जाएगा। हालांकि, खेल प्रेमियों के लिए एक राहत भरी खबर यह है कि मल्टी-नेशनल या अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स (जैसे वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, या ओलंपिक) में दोनों देश एक-दूसरे के खिलाफ खेलना जारी रखेंगे। सरकार ने साफ किया है कि यदि कोई तीसरा देश या अंतरराष्ट्रीय संस्था टूर्नामेंट आयोजित करती है, तो उसमें भागीदारी पर कोई रोक नहीं होगी।

सुरक्षा चिंताएं और ऐतिहासिक फैसलों का आधार

यह नीतिगत निर्णय अचानक नहीं लिया गया है। खेल मंत्रालय ने उल्लेख किया कि

यह नीति पिछले साल अगस्त में ही तैयार कर ली गई थी, जब एशिया कप के दौरान भारत और पाकिस्तान के खेलने को लेकर तीखी बहस छिड़ी हुई थी। सरकार का यह सख्त रुख सीमा पार से होने वाले तनाव और आतंकी घटनाओं के विरोध स्वरूप है। विशेष रूप से पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान गई थी, भारत ने पाकिस्तान के साथ सामान्य खेल संबंधों को बहाल न करने का कड़ा फैसला लिया था। मंत्रालय का मानना है कि जब तक सुरक्षा और कूटनीतिक स्थितियां सामान्य नहीं होतीं, तब तक द्विपक्षीय सीरीज संभव नहीं है।

मेजबानी के वैश्विक सपने : 2030 कॉमनवेल्थ और 2036 ओलंपिक पर नजर

भारत सरकार ने यह भी दोहराया कि वह खेल की दुनिया में एक 'ग्लोबल हब' बनना चाहता है। भारत की योजना 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों और 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी की दावेदारी पेश करने की है। इन बड़े वैश्विक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, सरकार अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मानकों का पालन करना चाहती है,जो यह कहता है कि बहुपक्षीय आयोजनों में किसी भी देश के एथलीट को आने से नहीं रोका जाना चाहिए। यही कारण है कि भारत ने बहुपक्षीय आयोजनों के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि एक जिम्मेदार खेल राष्ट्र के रूप में बनी रहे।

फैंस के लिए संदेश : रोमांच बना रहेगा,लेकिन शर्तों के साथ

खेल मंत्रालय के इस स्पष्टीकरण के बाद अब किसी भी प्रकार के भ्रम की गुंजाइश नहीं बची है। क्रिकेट फैंस जो सालों से भारत और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज या लंबी द्विपक्षीय सीरीज का इंतजार कर रहे थे, उन्हें अभी और प्रतीक्षा करनी होगी। हालांकि, आईसीसी के बड़े आयोजनों में भारत-पाक मुकाबला पहले की तरह ही देखने को मिलेगा। सरकार के इस संतुलित फैसले ने एक तरफ जहां राष्ट्रीय सुरक्षा और भावनाओं का सम्मान किया है, वहीं दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतिबद्धताओं को भी बरकरार रखा है। फिलहाल, खेल प्रेमियों की नजरें आगामी वैश्विक टूर्नामेंटों पर टिकी हैं जहां ये दोनों टीमें फिर से टकराती नजर आएंगी।

क्वीन सिरिकिट कप के लिए भारतीय टीम की अगुवाई करेंगी गुंतास कौर संधू

नई दिल्ली,06 मई 2026। इंडियन गोल्फ यूनियन (आईजीयू) क्वीन सिरिकिट कप में हिस्सा लेने के लिए तीन-सदस्यीय भारतीय टीम भेजेगा। यह इवेंट 12 से 15 मई तक इंडोनेशिया के बोगोर में सेंटुल हाइलैंड्स गोल्फ क्लब में आयोजित होगा। टीम की अगुवाई 2025 लेडीज ऑर्डर ऑफ मेरिट चैंपियन गुंतास कौर संधू करेंगी, जिन्होंने 2026 में भी लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। टीम की अन्य सदस्य हरियाणा की सीरत कंग और दिल्ली की केया बड्डु हैं। वंदना अग्रवाल बतौर मैनेजर टीम के साथ जाएंगी।

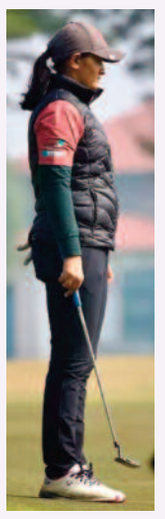

एशियन-पैसिफिक गोल्फ कॉन्फेडरेशन (एपीजीसी) द्वारा द आरएंडए (विश्व गोल्फ नियमों को नियंत्रित करने वाली संस्था) के सहयोग से आयोजित इस टूर्नामेंट में कुल 15 देश हिस्सा लेंगे, जिनमें मौजूदा चैंपियन साउथ कोरिया के साथ ऑस्ट्रेलिया, चीन, चीनी ताइपे, हांगकांग, भारत, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। 2025 लेडीज ऑर्डर ऑफ मेरिट चैंपियन गुंतास के नाम 2025-26 आईजीयू सीजन में 20 शुरुआतों में छह जीत और 17 बार टॉप-10 में जगह बनाने का रिकॉर्ड है। उन्होंने हाल ही में अप्रैल में आईजीयू वेस्ट बंगाल लेडीज और जूनियर गर्ल्स चैंपियनशिप में लेडीज और संयुक्त ए एंड बी कैटेगरी के खिताब जीते थे। क्वीन सिरिकिट कप को आधिकारिक तौर पर एमेच्योर लेडीज एशियन-पैसिफिक इनविटेशनल गोल्फ टीम चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम थाईलैंड की पूर्व रानी के नाम पर रखा गया है।

आईपीएल 2026 फाइनल अहमदाबाद में,31 मई को नरेंद्र मोदी स्टेडियम करेगा मेजबानी

अहमदाबाद,06 मई 2026। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के प्लेऑफ और फाइनल मुकाबलों का आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया है। सबसे बड़ी घोषणा के तहत यह पुष्टि की गई है कि इस सीजन का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 31 मई को खेला जाएगा। इस फैसले के साथ ही लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। बीसीसीआई ने बुधवार, 6 मई को प्लेऑफ मुकाबलों की मेजबानी स्थलों का भी ऐलान किया। बोर्ड के अनुसार इस बार क्वालिफायर 1 का आयोजन धर्मशाला में किया जाएगा, जबकि क्वालिफायर 2 और एलिमिनेटर मुकाबलों की मेजबानी न्यू चंडीगढ़ को सौंपी गई है। इस तरह प्लेऑफ चरण को अलग-अलग शहरों में आयोजित कर दर्शकों को विविध अनुभव देने की कोशिश की गई है। शुरुआत में फाइनल मुकाबले के लिए बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम को संभावित स्थल के रूप में चुना गया था। लेकिन बाद में कार्यक्रम में बदलाव करते हुए फाइनल की मेजबानी अहमदाबाद को दी गई। यह फैसला क्रिकेट प्रशंसकों के बीच चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि अहमदाबाद का यह स्टेडियम हाल के वर्षों में बड़े अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मैचों की मेजबानी कर चुका है।

आर्सेनल ने एटलेटिको मैड्रिड को हराकर चैंपियंस लीग फाइनल में जगह बनाई

बार्सिलोना,06 मई 2026। यूईएफ ए चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में आर्सेनल ने एटलेटिको मैड्रिड को 1-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। इस जीत के साथ ही आर्सेनल ने दो लेग के मुकाबले में 2-1 के कुल स्कोर से बढ़त हासिल की और टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। यह आर्सेनल के इतिहास में केवल दूसरी बार है जब टीम चैंपियंस लीग के फाइनल तक पहुंची है। इससे पहले क्लब साल 2006 में फाइनल में पहुंचा था,

जहां उसे बार्सिलोना के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। मैच में निर्णायक गोल कप्तान बुकायो साका ने किया, जिन्होंने पहले हाफ के ठीक खत्म होने से पहले एक आसान टैप-इन के जरिए गेंद को नेट में पहुंचाया। यह गोल मुकाबले का एकमात्र स्कोर साबित हुआ और इसी के दम पर आर्सेनल ने बढ़त बनाए रखी। इस मैच में आर्सेनल की डिफेंस भी मजबूत रही और टीम ने इस सीजन में अपनी नौवीं क्लीन शीट दर्ज की, जो उनकी लगातार बेहतर डिफेंसिव परफॉर्मेंस को दर्शाता है। घरेलू मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में टीम ने पूरे मैच के दौरान संतुलित खेल दिखाया और एटलेटिको मैड्रिड को ज्यादा मौके नहीं दिए।

आईपीएल 2026 फाइनल बेंगलुरु से अहमदाबाद शिफ्ट

बेंगलुरु,06 मई 2026। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के फाइनल मुकाबले को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है। बेंगलुरु स्थित एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम से फाइनल की मेजबानी छीन ली गई है और अब यह हाई-प्रोफाइल मुकाबला अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा। यह फैसला लोकल अधिकारियों और स्टेकहोल्डर्स की विवादित मांगों और आयोजन से जुड़ी चिंताओं के चलते लिया गया है। सूत्रों के अनुसार,आईपीएल अधिकारियों और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के बीच लगातार बातचीत चल रही थी। हालांकि, बातचीत के दौरान कई मांगों को लेकर सहमति नहीं बन पाई। इनमें सदस्यों और स्थानीय नेताओं के लिए अतिरिक्त पास की मांग भी शामिल थी, जिसे अधिकारियों ने अनावश्यक और अस्वीकार्य बताया।

सीजीपीएससी घोटाला : आरोपी उत्कर्ष की अग्रिम जमानत खारिज

25 लाख लेकर एग्जाम पास करवाया,मामला दर्ज होने के बाद से फरार है...

बिलासपुर,06 मई 2026। छत्तीसगढ़ पीएससी 2022 के कैंडिडेट से 25 लाख लेकर परीक्षा पास कराने वाले एक आरोपी की अग्रिम जमानत हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। सीबीआई जांच में सामने आया है कि,रायपुर शांति नगर के रहने वाले उत्कर्ष चंद्राकर ने बड़ी रकम लेने के बाद 30-35 कैंडिडेट्स को प्री और मेंस के क्वेश्चन पेपर दिए थे। हालांकि इस डील में कई लोग शामिल थे। उत्कर्ष पर ये मामला दर्ज होने के बाद से वह फरार है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि पेपर लीक करना मेहनत करने वाले युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। बता दें कि इस घोटाले में सीबीआई ने अपनी अंतिम चार्जशीट में कुल 29 लोगों को आरोपी बनाया है,जिसमें सीजीपीएससी का तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी मास्टमाइंड है, वह जेल में हैं।

गवाह ने बताया...बस में भरकर ले गए थे बारनवापारा

मामले की अहम गवाह सुषमा अग्रवाल ने धारा 164 के तहत दिए बयान में कई खुलासे किए हैं। उसने बताया कि उत्कर्ष ने उससे 25 लाख रुपए लिए थे। 8 मई 2022 को बुक की गई बस से उम्मीदवारों को बारनवापारा रिजॉर्ट ले जाया गया,जहां लीक प्रश्नपत्रों के जरिए मुख्य परीक्षा की तैयारी करवाई गई।

50-60 लाख मांगे,परीक्षा की तैयारी भी करवाई...

आरोप है कि उत्कर्ष चंद्राकर ने चयन के बदले उम्मीदवारों से 50 से 60 लाख रुपए तक की मांग की थी। परीक्षा से पहले उम्मीदवारों को रायपुर के सिद्धि विनायक पैलेस, बारनवापारा रिजॉर्ट और होटल वेंकटेश इंटरनेशनल में ठहराया गया था। प्रारंभिक परीक्षा से एक दिन पहले 12 फरवरी 2022 को उत्कर्ष ने उम्मीदवारों को प्रश्नपत्र और उसके जवाब दे दिए थे। मुख्य परीक्षा के समय भी मोबाइल से प्रश्नपत्र मंगवाकर रिजॉर्ट में ठहरे उम्मीदवारों को याद कराया जाता था।

सीबीआई की जांच में क्या सामने आया?

सीबीआई के मुताबिक,टामन ने परीक्षा के पर्चे अपने घर पर साहिल,नीतेश, उसकी पत्नी निशा कोसले और दीपा आडिल को दिए। इसके बाद उप परीक्षा नियंत्रक ललित गणवीर ने लीक हुआ पेपर बजरंग पावर एंड इस्पात कंपनी के डायरेक्टर श्रवण गोयल को सौंपा। श्रवण गोयल के बेटे शशांक और बहू भूमिका ने इसी लीक पेपर से तैयारी की। परिणामस्वरूप दोनों डिप्टी कलेक्टर बन गए।

कोलकाता से रायपुर तक साजिश

प्रश्नपत्र छापने का काम कोलकाता की एक प्रिंटिंग कंपनी को दिया गया था। जनवरी 2021 में कंपनी का कर्मचारी महेश दास 7 सेट प्रश्नपत्र लेकर रायपुर आया। उसने ये सभी पर्चे आरती वासनिक को सौंपे।

छत्तीसगढ़ में 43 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर

7 जिलों के कलेक्टर बदले,विश्वदीप को बीजापुर की जिम्मेदारी

रायपुर,06 मई 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने 43 आईएएस अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां की हैं। कई अहम विभागों के प्रमुख बदले गए हैं और 7 जिलों में नए कलेक्टरों की तैनाती की गई है। जारी आदेश के अनुसार, अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रभार दिया गया है, जबकि मनोज कुमार पिंगुआ को वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निहारिका बारिक को गृह एवं जेल विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। शहला निगार को महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ समाज कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सचिव स्तर पर भी बड़े बदलाव किए गए हैं। डॉ. रोहित यादव को वित्त विभाग, कमलप्रीत सिंह को स्कूल शिक्षा विभाग और परदेशी सिद्धार्थ कोमल को कृषि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं सारांश मित्तर को CREDA का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाते हुए ऊर्जा विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कोरिया में पुष्पा साहू, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में संतन देवी जांगड़े, सूरजपुर में रेना जमील और बीजापुर में विश्वदीप को नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सारंगढ़-बिलाईगढ़ में पद्मिनी भोई साहू को कलेक्टर बनाया गया है।

छत्तीसगढ़ में IAS अफसरों के तबादले

अधिकारी का नाम	नई पदस्थापना / जिम्मेदारी
ऋचा शर्मा	अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास + DG, SIRD + विकास आयुक्त
मनोज कुमार पिंगुआ	अपर मुख्य सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन
सुबोध कुमार सिंह	प्रमुख सचिव, ऊर्जा + चेयरमैन, पावर कंपनीज (अतिरिक्त)
निहारिका बारिक	प्रमुख सचिव, गृह एवं जेल
शहला निगार	प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास + समाज कल्याण (अतिरिक्त)
डॉ. रोहित यादव	सचिव, वित्त + जनसंपर्क (अतिरिक्त)
डॉ. कमलप्रीत सिंह	सचिव, स्कूल शिक्षा
परदेशी सिद्धार्थ कोमल	सचिव, कृषि + कृषि उत्पादन आयुक्त
रीना कंगाले	सचिव, खाद्य + वाणिज्यिक कर (आबकारी अतिरिक्त)
अविनाश चंपावत	सचिव, सामान्य प्रशासन + उच्च शिक्षा (अतिरिक्त)
मुकेश कुमार बंसल	सचिव, वाणिज्यिक कर + PWD + विमानन + CM सचिवालय (अतिरिक्त)
आर. संगीता	सचिव, नगरीय प्रशासन
अंकित आनंद	सचिव, आवास एवं पर्यावरण (पंजीयन प्रभार हटाया गया)
भुवनेश यादव	सचिव, योजना + वाणिज्यिक कर (पंजीयन अतिरिक्त)
एस. भारतीदासन	सचिव, पर्यटन + संस्कृति + धार्मिक न्यास
शम्मी आबिदी	सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन
बसवराजू एस	सचिव, कौशल विकास
कैसर अब्दुलहक	मिशन संचालक, जल जीवन मिशन (अतिरिक्त)
राजेश सिंह राणा	सचिव, ग्रामोद्योग + MD हस्तकरघा
महादेव कावरे	आयुक्त, सहकारिता
श्याम लाल धावड़े	आयुक्त, रायपुर संभाग
सारांश मित्तर	CEO, CREDA + सचिव, ऊर्जा (अतिरिक्त)
पदुम सिंह एल्मा	आयुक्त, आबकारी
संजीव कुमार झा	MD, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (अतिरिक्त)
रणबीर शर्मा	संचालक, समाज कल्याण
पुष्पा साहू	कलेक्टर, कोरिया
राजेंद्र कुमार कटारा	विशेष सचिव, स्वास्थ्य + आयुष
संतोष देवांगन	कलेक्टर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही
एस. जयवर्धन	संचालक, कोष एवं लेखा
प्रभात मलिक	संयुक्त सचिव, CM + उद्योग + विमानन
डॉ. राहुल वेंकट	आयुक्त, आदिम जाति + सचिव, PSC
चंदन संजय त्रिपाठी	कलेक्टर, बलरामपुर
रोक्तिमा यादव	आयुक्त, उच्च शिक्षा
लीना मण्डावी	MD, खादी बोर्ड
संतन देवी जांगड़े	कलेक्टर, MCB (मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर)
डॉ. संजय कन्नौजे	संचालक, संस्कृति
पद्मिनी भोई साहू	कलेक्टर, सारंगढ़-बिलाईगढ़
संबित मिश्रा	आयुक्त, नगर निगम रायपुर
रेना जमील	कलेक्टर, सूरजपुर
विश्वदीप	कलेक्टर, बीजापुर
गीता यादव	सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल
ऋषभ पाराशर	संचालक, बजट + स्थानीय निधि (अतिरिक्त)
मयंक अग्रवाल	CEO, CHIPS

रायपुर मर्डर केस : इलाज के दौरान दूसरी साली ने भी तोड़ा दम,कातिल जीजा ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण

रायपुर,06 मई 2026। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मोवा क्षेत्र में एक बाउंसर ने अपनी दो सालियों की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी जितेंद्र वर्मा अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था, जिससे परेशान होकर उसकी पत्नी बच्चों के साथ मायके चली गई थी। मंगलवार रात जितेंद्र नशे की हालत में अपनी लाइसेंसी पिस्टल लेकर ससुराल पहुंचा और बच्चों से मिलने की जिद करने लगा। जब उसकी सालियों, गीतांजलि और दुर्गेश्वरी ने उसे समझाने का प्रयास किया, तो जितेंद्र ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। माथे पर गोली लगने से गीतांजलि की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल दुर्गेश्वरी ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने सड़क पर हवाई फायरिंग की और फिर खुद थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया।

छत्तीसगढ़ के नए मुख्य आयकर आयुक्त बनाए गए संजीव कुमार

रायपुर,06 मई 2026। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने देश भर 57 आयकर आयुक्त और महानिदेशक आयकर अन्वेषण के तबादले किए हैं। केंद्रीय राजस्व विभाग से जारी आदेशानुसार संजीव कुमार छत्तीसगढ़ के नए मुख्य आयुक्त होंगे। वे दिल्ली से स्थानांतरित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक पदस्थ रहे देवरत्न कुमार के 30 अप्रैल को रिटायर होने से हुई रिक्ति पर नई नियुक्ति की गई है। संजीव कुमार अब तक दिल्ली में ओएसडी थे। इसी तरह से सीजी एमपी सर्किल के इंदौर रीजन में तरूण सीम नए आयुक्त होंगे।

नाबालिग प्रेमी-प्रेमिका ने ट्रेन के सामने कूदकर दी जान,क्षेत्र में फैली सनसनी

बालोद,06 मई 2026। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक ऐसी दर्दनाक खबर सामने आई है, जिसने प्रेम और जिद के बीच की खतरनाक रेखा को उजागर कर दिया। साथ जीने-मरने की कसमें खाने वाले एक प्रेमी जोड़े ने अपनी कहानी का अंत रेल की पटरी पर लिख दिया। चोरहापड़ाव रेलवे स्टेशन के पास बुधवार सुबह जब लोगों की नजर ट्रैक पर पड़ी, तो दिल दहला देने वाला मंजर सामने था। एक नाबालिग लड़की और युवक के शव क्षत-विक्षत हालत में पड़े थे। कुछ ही देर में इलाके में सनसनी फैल गई और सूचना मिलते ही जीआरपी मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि दोनों एक-दूसरे से प्रेम करते थे। मृतकों की पहचान कुम्हालोरी गांव निवासी 20 वर्षीय जितेश्वर तारम और डौंडी ब्लॉक के साल्हे गांव की 16 वर्षीय लिलिसा उइके के रूप में हुई है।

महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल

कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने पर किया प्रदर्शन,कहा- भाजपा की केंद्र सरकार को नहीं है जनता की परवाह

बिलासपुर,06 मई 2026। बढ़ती महंगाई और एलपीजी सिलेंडर के दामों में भारी बढ़ोतरी के विरोध में बिलासपुर जिला कांग्रेस ने मंगलवार को नेहरू चौक पर प्रदर्शन किया। शाम के समय बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन से नेहरू चौक तक पदयात्रा निकाली। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए नेहरू चौक पर विरोध-प्रदर्शन किया और भाजपा की केंद्र-राज्य सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। जिला शहर अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने कमर्शियल उपयोग वाले 19 किलो एलपीजी सिलेंडर के दाम में 993 रुपए की अभूतपूर्व बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में इतनी बड़ी एकमुश्त वृद्धि पहले कभी नहीं हुई। सिलेंडर की कीमत 3100 से 3200 रुपए तक पहुंचने से इसका सीधा असर आम आदमी की थाली पर पड़ रहा है।

महंगाई से हर वर्ग के लोग परेशान

जिला ग्रामीण अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री ने कहा कि महंगाई से छोटे ढाबा संचालक, ठेला व्यापारी,स्ट्रीट फूड विक्रेता और मध्यमवर्गीय परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि कीमतें कम नहीं हुईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

महंगाई के विरोध जारी रहेगा आंदोलन

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लगातार बढ़ती कीमतों से आम जनता त्रस्त है। छोटे व्यापारियों, ढाबा संचालकों और मध्यमवर्गीय परिवारों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक कीमतों में कमी नहीं होती, तब तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस भवन में एकत्रित हुए, जहां से पदयात्रा करते हुए नेहरू चौक पहुंचे। हाथों में बैनर, पोस्टर और झंडे लेकर कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में मौजूद भीड़ के कारण पूरा चौक आंदोलन स्थल में तब्दील हो गया और आसपास के लोग भी रुककर प्रदर्शन देखने लगे।

छत्तीसगढ़ में महिलाओं को जमीन रजिस्ट्री पर 50% की छूट,राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित

रायपुर,06 मई 2026। छत्तीसगढ़ में जमीन और मकान की रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी में महिलाओं को 50 प्रतिशत छूट की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। साय सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में यह कदम उठाया है। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिलाओं के लिए संपत्ति रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देने का फैसला लिया गया था। इसकी अधिसूचना अब राजपत्र में प्रकाशित हो गई है। अब महिलाओं के लिए संपत्ति खरीदना आसान और सस्ता होगा और परिवारों को भी संपत्ति महिलाओं के नाम पर दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। राज्य सरकार के अनुसार, इस फैसले से करीब 153 करोड़ रुपये के राजस्व का असर पड़ सकता है।

भू-माफियाओं के आतंक से त्रस्त किसान 'न्याय दो या इच्छा मृत्यु' की गुहार...

धमतरी,06 मई 2026। धमतरी जिले के रत्ना बांधा क्षेत्र से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां भू-माफियाओं के कथित दबाव और प्रशासनिक उदासीनता से परेशान किसानों ने 'इच्छा मृत्यु' की मांग कर दी है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला, तो वे कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मदाह या जहर सेवन जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। पीड़ित किसानों का कहना है कि रत्ना बांधा स्थित उनकी पुश्तैनी कृषि भूमि तक जाने वाला लगभग 100 वर्ष पुराना रास्ता पंचवटी कॉलोनी के पीछे से गुजरता था, जिसे अब दीवार खड़ी कर बंद कर दिया गया है। इस कारण किसान न तो ट्रैक्टर या हार्वेस्टर ले जा पा रहे हैं और न ही आसानी से खेत तक पहुंच पा रहे हैं। इससे उनकी खेती और आजीविका दोनों पर गंभीर असर पड़ा है। किसानों ने आरोप लगाया है कि कुछ रसूखदार भू-माफिया और दलाल उन्हें लगातार जमीन बेचने के लिए दबाव बना रहे हैं। उनका कहना है कि 'जमीन नहीं बेचोगे तो रास्ता कभी नहीं खुलेगा' जैसी धमकियां दी जा रही हैं। किसानों का साफ कहना है कि वे किसी भी हालत में अपनी जमीन नहीं बेचेंगे। किसानों के अनुसार, पूर्व में जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

3 गांजा तस्करों को पांच-पांच साल की सजा

14 किलो से अधिक गांजा मिला था,कोर्ट ने कहा...राज्य में बढ़ रहा नशा,नरमी नहीं

रायपुर,06 मई 2026। रायपुर के धरसींवा थाना क्षेत्र में गांजा तस्करी के मामले में विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने 3 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 5-5 साल के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसला विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने सुनाया। सरकारी वकील के.के. चन्द्राकर ने बताया कि, 11 सितंबर 2022 को पुलिस सहायता केंद्र सिलतरा के उपनिरीक्षक प्रियेश जॉन को सूचना मिली थी कि इंडेन ऑयल पेट्रोल पंप के पास सर्विस रोड पर तीन युवक बैग में गांजा लेकर बिक्री के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं। पुलिस टीम ने स्वतंत्र गवाहों को साथ लेकर मौके पर दबिश दी और तीनों संदिग्धों को घेराबंदी कर पकड़ा। तलाशी के दौरान तीनों के पास से अलग-अलग बैग और झोले में गांजा बरामद हुआ। राहुल उर्फ आशीष द्विवेदी के पास से 5 किलो 300 ग्राम, अमन शुक्ला के पास से 4 किलो 800 ग्राम और विनीत द्विवेदी के पास से 4 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। कुल मिलाकर करीब 14 किलो 500 ग्राम गांजा जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के तहत उनके अधिकार बताए।

लॉकअप में बंद हिस्ट्रीशीटर हुआ Instagram में Live,खुद को बिलासपुर का किंग बताया

बिलासपुर,06 मई 2026। सकरी थाने के लॉकअप से एक हिस्ट्रीशीटर का इंस्टाग्राम लाइव वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। वायरल वीडियो में आरोपी सिगरेट पीते हुए नजर आ रहा है। उसके साथ जेल में तीन अन्य आरोपी भी दिखाई दे रहे हैं। सोमवार दोपहर इंस्टाग्राम के 'जय माता दी' पेज पर यह वीडियो पोस्ट किया गया। इसमें हिस्ट्रीशीटर विक्की पांडेय लॉकअप के अंदर से लाइव होकर खुद को 'किंग ऑफ बिलासपुर' बताता दिख रहा है। वीडियो में उसने सीसीटीवी कैमरे, लॉकअप के अंदर के दृश्य और थाना प्रभारी के कक्ष तक का नजारा भी दिखाया। दोपहर 12:30 बजे वीडियो पोस्ट होते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई।

बघेल के आरोप और झा का पलटवार, 'छत्तीसगढ़ संवाद' विवाद से गरमाई प्रदेश की सियासत

एआई वीडियो और सोशल मीडिया संचालन को लेकर पूर्व सीएम के गंभीर आरोप...भाजपा नेता ने दी सलाह...'धमकी नहीं,मुद्दों पर करें राजनीति'

-न्यूज डेस्क-

रायपुर,06 मई 2026। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भाजपा नेता पंकज कुमार झा के बीच सोशल मीडिया और 'छत्तीसगढ़ संवाद' को लेकर तीखा शब्दवार सामने आया है,जिससे प्रदेश की सियासत में नया विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर स्थित 'छत्तीसगढ़ संवाद' को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इसे अब 'भाजपा कार्यालय,नवा रायपुर' का बोर्ड लगा लेना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि गुजरात की एजेंसियों के माध्यम से एआई वीडियो बनाकर उनकी और अन्य कांग्रेस नेताओं की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। बघेल ने आरोप लगाया कि उक्त संस्थान अब एक तरह से 'प्रोडक्शन हाउस' बन गया है, जहां से न केवल राजनीतिक वीडियो तैयार हो रहे हैं,बल्कि विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट्स का संचालन और पोस्टिंग भी की जा रही है। उन्होंने सत्तापक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अंदरूनी बैठकों में भले ही बातें छिपाने की कोशिश की जाती हो,लेकिन 'दीवारों के भी कान होते हैं।' बघेल ने अपने बयान में तंज कसते हुए कहा कि संबंधित लोग 'खाकी पैंट पहनकर कमल का बिल्ला लगा लें और कार्यालय का नाम बदल दें।' उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि समय के साथ हर साजिश का हिसाब होगा–'घड़ी रुकने से समय नहीं रुकता।' वहीं,बघेल के इन आरोपों पर भाजपा नेता पंकज कुमार झा ने तीखा पलटवार करते हुए उन्हें 'मुफ्त की सलाह' दी। झा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को अपने सलाहकारों को बदल लेना चाहिए, क्योंकि मौजूदा सलाहकार उनकी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। झा ने अपने बयान में कहा कि भाजपा को प्रचार-प्रसार के लिए किसी शासकीय संस्थान की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने दावा किया कि वे स्वयं 'संवाद' में बैठते हैं और पूर्व सरकार के दौरान वहां क्या गतिविधियां होती थीं, इसकी पूरी जानकारी रखते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को लेकर दबाव बनाया जाता था, यहां तक कि लोगों को जेल भेजने और राजद्रोह जैसे गंभीर मामलों में फंसाने तक की कार्रवाई की जाती थी। भाजपा नेता ने कहा कि इन सबके बावजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की नीतियों, वादाखिलाफी और कथित घोटालों को जनता तक पहुंचाया। उन्होंने यह भी कहा कि उस दौर में शासकीय संसाधनों के उपयोग के बावजूद विपक्ष प्रभावी जवाब देने में सफल नहीं हो पाया। झा ने आगे कहा कि केवल आक्रामक बयानबाजी, धमकी या 'चमकी' की भाषा से कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलता। उन्होंने बघेल को सलाह दी कि वे सोशल मीडिया पर अशालीन भाषा और गैर-गंभीर टिप्पणियों से बचें तथा ठोस और जनहित के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने यह भी कहा कि 'फेसबुक पोस्ट लिखने वालों' को भी बदलने की जरूरत है, क्योंकि वर्तमान में भाषा और स्तर दोनों ही राजनीतिक गरिमा के अनुरूप नहीं हैं। अपने बयान के अंत में झा ने परोक्ष रूप से बघेल को संयम बरतने की सलाह देते हुए कहा कि 'ऐसी वैसी बातों से बेहतर है खामोश रहो, या कुछ ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो।'

राजनीतिक माहौल हुआ गरम

दोनों नेताओं के बीच इस तरह की तीखी बयानबाजी से प्रदेश की राजनीति में गर्माहट बढ़ गई है। एक ओर जहां बघेल ने सत्तापक्ष पर तकनीकी माध्यमों के दुरुपयोग और साजिश के आरोप लगाए हैं,वहीं भाजपा की ओर से इन आरोपों को खारिज करते हुए पलटवार किया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में यह विवाद और गहराने की संभावना है, क्योंकि सोशल मीडिया और एआई जैसे मुद्दे अब राजनीतिक रणनीति के अहम हिस्से बनते जा रहे हैं। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहने के संकेत मिल रहे हैं।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)